आषाढ़ कृष्ण पक्ष- 3, 2083 | dopaharmetro | epaper.dopaharmetro.com | dopaharmetro | वर्ष-09, अंक - 357 | पेज 8, मूल्य 2 रुपए

डाक पंजीयन क्रमांकः म।प्र।/4-474/2024-26

भोपाल

02 जुलाई 2026 गुरुवार

आज का मौसम

30.5 अधिकतम

22.2 न्यूनतम

बेबाक खबर हर दोपहर

दोपहर मेट्रो

Page-7

आस्था, राजनीति और 2027 का चुनाव...किसके लिए सबसे बड़ी चुनौती?

दोपहर मेट्रो पड़ताल

● राजेश सिरोठिया

अयोध्या कांडः पार्ट- 3

अयोध्या का राम मंदिर केवल एक धार्मिक परिसर नहीं है। यह भारतीय राजनीति, सांस्कृतिक चेतना और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए यहाँ घटित कोई भी विवाद स्वाभाविक रूप से राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाता है। विपक्ष इस प्रकरण को सरकार की जवाबदेही से जोड़कर देख रहा है, जबकि सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह निष्पक्ष जांच कराकर यह संदेश दे कि आस्था के केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह संतुलन जितना प्रशासनिक है, उतना ही राजनीतिक भी।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक और प्रश्न खड़ा किया है। क्या यह मामला केवल कुछ व्यक्तियों तक सीमित रहेगा, या इससे ट्रस्ट की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की शुरुआत होगी? यदि जांच केवल दोष तय करने तक सीमित रही और संस्थागत सुधार पीछे रह गए, तो भविष्य में ऐसे विवाद फिर जन्म ले सकते हैं। भाजपा के लिए भी यह सामान्य राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम मंदिर उसके वैचारिक और राजनीतिक सफर का केंद्रीय प्रतीक रहा है। इसलिए इस विषय पर पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, राजनीतिक आवश्यकता भी है।

दूसरी ओर, विपक्ष इस मुद्दे को सत्ता की जवाबदेही के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। आने वाले महीनों में यह टकराव और तीखा हो सकता है, लेकिन चुनावी लाभ-हानि से ऊपर एक प्रश्न है - क्या इस पूरे प्रकरण के बाद श्रद्धालुओं का विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा? इसका उत्तर किसी राजनीतिक दल के पास नहीं, बल्कि जांच की निष्पक्षता, ट्रस्ट की पारदर्शिता और व्यवस्था में किए जाने वाले सुधारों के पास है। राम मंदिर आंदोलन ने भारत की राजनीति बदल दी थी। अब राम मंदिर की प्रशासनिक विश्वसनीयता की परीक्षा है। यदि इस संकट से सीख लेकर जवाबदेही की नई परंपरा स्थापित होती है, तो यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सकारात्मक परिणाम होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो सवाल केवल व्यक्तियों पर नहीं, पूरी व्यवस्था पर उठते रहेंगे। जारी...

एमपी में मानसून की बढ़ी रफ्तार

आज प्रदेश के 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सागर और भोपाल संभाग के कई जिलों को कवर करने के बाद आज इसके उज्जैन और ग्वालियर-चंबल संभाग तक पहुंचने की संभावना है।

मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 40 से ज्यादा जिलों में गरज-चमक और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं अशोकनगर, देवास, खंडवा, बैतूल, सागर, मंडला और डिंडौरी में भारी बारिश का यलो अलर्ट है।

भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, झाबुआ, आलीराजपुर, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, गुना, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी सहित कई जिलों में आज बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है।

मंदिर में चोरी... ट्रस्ट के महासचिव को आरोपी नहीं गवाह मानकर चल रही है पुलिस

चंपत राय का छलका दर्द, बोले... मेरे साथ धोखा हुआ मैंने ही चोरी पकड़ने के लिए लगवाए थे गुप्त कैमरे

अयोध्या, एजेंसी

राम मंदिर दान चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इस्तीफ़ा दे चुके जनरल सेक्रेटरी चंपत राय से बुधवार को करीब दो घंटे तक बंद कमरे में पूछताछ हुई। इस दौरान उन्होंने अपना बचाव करते हुए कहा कि ने उन्होंने ही सर्विलांस कैमरे लगवाकर चोरी का पता लगाया था। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने पुलिस से कहा कि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था, उन्होंने ही उन्हें 'धोखा' दिया। भक्तों के चंदे के कथित गबन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। पुलिस पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा, मैंने चोरी रोकने की कोशिश की लेकिन मेरे ही साथ ही धोखा हो गया। पुलिस ने अनिल मिश्रा से भी अलग से पूछताछ की।

सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं ने अनिल मिश्रा से मंदिर के कामकाज, दान संभालने के तरीकों और वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज मांगे। वहीं चंपत राय से चोरी का मामला सामने आने के बाद हुई घटनाओं के क्रम, दान की गिनती करने वाले सिस्टम के कामकाज और ट्रस्ट की अंदरूनी प्रतिक्रिया के बारे में पूछताछ की गई। फिलहाल पुलिस चंपत राय को एक अहम गवाह मान रही है और एफआईआर में उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दान संभालने में कोई प्रक्रियात्मक चूक हुई थी या नहीं और क्या मौजूदा सुरक्षा उपाय पर्याप्त थे।

चंपत राय का दावा इस मामले की शुरुआती घटनाओं में से एक से मेल खाता है। सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट के अधिकारियों को तब गड़बड़ी का शक हुआ जब उन्हें मिले दान और बैंक में जमा की गई रकम के बीच बार-बार अंतर दिखाई दिया। यह पता लगाने के लिए कि क्या गिनती के दौरान पैसे की हेराफेरी हो रही थी, दान की गिनती वाले कमरे में कथित तौर पर छिपे हुए कैमरे लगाए गए थे जिकी जानकारी गिनती में लगे लोगों को नहीं थी। कथित तौर पर इस गुप्त निगरानी में कर्मचारियों को दान का आधिकारिक हिसाब होने से पहले ही कैश और गहने चुराते हुए पकड़ा गया, जिससे जांचकर्ताओं को इस कथित रैकेट का पहला ठोस सबूत मिला। पुलिस का मानना है कि निगरानी फुटेज से कई आरोपियों की पहचान करने में मदद मिली।

ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास ने कहा - पूरी गलती निर्माण प्रभारी गोपाल राव की

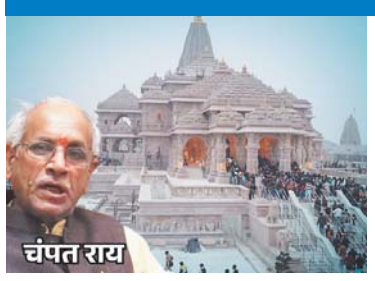

अविनाश शुक्ला किंगपिन, रिमांड पर लेने की तैयारी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस इस पूरे मामले का किंगपिन मान रही है। इसलिए उसे 48 घंटे के लिए कस्टडी रिमांड में लेने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई है। मामले के विवेचक डीएसपी आशुतोष तिवारी की तरफ से कोर्ट में दाखिल हुई इस अर्जी पर एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट अयोध्या में आज सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि अविनाश जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकता है। छापेमारी में अविनाश के घर से 20.39 लाख रुपए और 1121 डॉलर हुए बरामद हुए थे।

आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर

पहली बार, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज सामने आए हैं। उन्होंने कहा- पूरी गलती गोपाल राव की है। वे राजनीति कर रहे हैं। वो सबको उलझा देते हैं। वो राम की परंपरा नहीं मानते हैं। गोपाल राव राम मंदिर के निर्माण प्रभारी और ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य हैं। मूलरुप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। उधर, खबर है कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है। प्रशासन ने आरोपियों के नए घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे घरों की पहचान कर ली है, जिनका नक्शा पास नहीं है या जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। रडार पर आरोपियों के वो घर हैं, जो उन्होंने मंदिर में नौकरी के बाद बनवाए हैं। आरोपी लवकुश मिश्रा का शहादतगंज में बन रहा मकान और अनुकल्प मिश्रा के कौशलपुरी स्थित मकान पर बुलडोजर चल सकता है।

आईएसआई का फंडिंग नेटवर्क चलाने वाला एजेंट गिरफ्तार

जयपुर, एजेंसी

राजस्थान पुलिस की सीआईडी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए फंडिंग नेटवर्क चलाने वाले एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपित रफीक चांद शेख जासूसी गतिविधियों में शामिल लोगों तक आईएसआई की ओर से भेजे जाने वाले रुपये पहुंचा रहा था।

सीआइडी इंटेलिजेंस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि जनवरी में जैसलमेर निवासी झाबराराम और असम के डिब्रूगढ़ वायुसेना स्टेशन पर एमटीएस पद पर तैनात सुमित कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पर भारतीय सेना से संबंधित गोपनीय सूचनाएं आईएसआई के हैंडलरों तक पहुंचाने का आरोप है। आरोपितों को जासूसी के बदले आईएसआई की ओर से रुपए रफीक ने भेजे थे। इसके बाद सीआईडी ने रफीक से पूछताछ की।

न्यूज विंडो

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बने वायु सेना के वाइस चीफ

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तौर पर काम करने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वाइस चीफ आफ एयर स्टाफ का पद संभाल लिया। उन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर की जगह ली है, जो वायु सेना में चार दशक की सेवा के बाद 30जून को रिटायर हो हुए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह अगले चीफ आफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ बनने वाले हैं। एयर मार्शल दीक्षित को वायु भवन में गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

आसाराम को इलाज के लिए एक महीने की मिली अनुमति

जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एक माह तक उपचार के लिए समय दिया है। आसाराम का जोधपुर के आरोग्यं अस्पताल में उपचार चल रहा है। आसाराम की ओर से उपचार के लिए अवधि बढ़ाने की याचिका दायर की गई थी। याचिका पर जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने सुनवाई की और अवधि बढ़ाने की याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने साथ ही सरकार से चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।

आज का कार्टून

जापान की प्रधानमंत्री तकाइची से मिले पीएम मोदी

नईदिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देश के पीएम ने अपने अपने मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल से मिलवाया। इससे पहले सनाए ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया।

सिखों को हेलमेट पहनने से छूट धर्म के आधार पर नहीं

मुंबई, एजेंसी

बांबे हाई कोर्ट ने पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों को दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनने से मिली छूट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह छूट धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उचित वर्गीकरण के आधार पर दी गई है। नागपुर बेंच की जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के और जस्टिस निवेदिता मेहता ने छात्र कीर्तेश चौधरी की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के एक प्रविधान को चुनौती दी थी और यह दावा किया था कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले...

विभाजन के समय पाकिस्तान से आए लोग शरणार्थी नहीं, संघर्ष के योद्धा थे

नागपुर, एजेंसी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को केवल शरणार्थी कहना उनके संघर्ष के साथ न्याय नहीं होगा। उन्होंने उन्हें 'संघर्ष के योद्धा' बताते हुए कहा कि इन लोगों ने मातृभूमि और अपने धर्म के प्रति अटूट आस्था के कारण अपार कष्ट सहते हुए भारत आने का निर्णय लिया। वे पाकिस्तान में अपनी संपत्ति, व्यवसाय और सुविधाएं छोड़कर ऐसे देश में आए, जहां वे निर्भय होकर अपनी आस्था के साथ जीवन जी सकें।

नागपुर में सिंधु एजूकेशन सोसाइटी के 75वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि विभाजन के बाद विस्थापित हुए लोग परिस्थितियों के शिकार जरूर थे, लेकिन वे पराजित नहीं थे।

उन्होंने करियर और धन के बजाय राष्ट्र और धर्म को प्राथमिकता दी, इसलिए वे संघर्ष के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में कठिनाइयां हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में हार मानने के बजाय दोबारा उठकर आगे बढ़ने वाला ही अंततः सफल होता है। शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए भागवत ने कहा कि मूल्य-आधारित शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि शिक्षकों के आचरण और संस्कारों से मिलती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ऐसी जागरूक और जिम्मेदार पीढ़ी तैयार करना है, जो समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य करे।

सक्सेस स्टोरी

लगातार असफलता पर परिवार ने कह दिया था, चाहे कुछ भी कर लो अब पढ़ाई नहीं करना

12 साल इंतजार, 40 परीक्षाओं में फेल... आखिर मिली अफसर की कुर्सी

इंदौर, एजेंसी

कहते हैं सफलता अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है, जो बार-बार मिलने वाली असफलताओं के बाद भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। मनोज पाल की कहानी इसी जज्बे और धैर्य की मिसाल है। उन्हें कई बार नाकामियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि अब पढ़ाई मत करो, चाहे कुछ भी कर लो। क्योंकि वह लगातार 40 परीक्षाओं में फेल हो चुके थे। लेकिन, वह रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। 12 साल बाद एक दिन ऐसा आया जबा उनका सपना पूरा हुआ। वह MPPSC क्रैक करके अफसर बने।

मनोज पाल मध्य प्रदेश के एक गांव के रहने वाले हैं। वह एक साधारण किसान परिवार से आते हैं। एक वीडियो में वह बताते हैं कि उनकी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई थी, जहां सुविधाएं सीमित थीं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने के कारण उन्होंने ठान लिया था कि वह सरकारी नौकरी हासिल करके अपना और अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाएंगे।

एमपीपीएससी की तैयारी के साथ-साथ मनोज ने वन-डे एग्जाम की तैयारी भी शुरू की थी। शुरुआती प्रयास में उन्होंने फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा पास कर ली थी लेकिन फिजिकल नहीं निकाल पाए। इसके बाद उन्होंने पीएससी और अन्य कई एग्जाम देने का फैसला किया। क्योंकि उनका लक्ष्य था कि किसी भी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए। मनोज बताते हैं कि उन्होंने लगभग 40 परीक्षाएं दीं और इन सभी में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। कई बार तो वह कुछ अंकों से एग्जाम पास नहीं कर पाए। एमपीपीएससी के 6 प्रयास में असफल होने के बाद वह बहुत निराश हुए लेकिन उनके दोस्त आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती रही। इसके बाद वह हिम्मत जुटाते और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते।

सातवें अटेम्प्ट में मिली सफलता

बार-बार मिलीं असफलताओं के बीच मनोज को समाज और आसपास के लोगों के तानों का भी सामना करना पड़ा। वह बताते हैं कि इतनी बार फेल होने के बाद उनके घरवालों की तरफ से भी निराशाभरी बातें सुनने को मिलने लगीं। उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष जारी रखा। MPPSC के 7वें प्रयास में उनका इंतजार खत्म हुआ और उन्होंने 2024 की परीक्षा में रैंक -15 हासिल करके अपना सपना पूरा किया। कड़ी मेहनत, अनुशासन और कई साल के इंतजार के बाद अधिकारी बने। अभी वह फाइनेंस विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी सफलता की कहानी लंबे संघर्ष और अटूट विश्वास की यात्रा है।

नए कानूनों के दो साल... तकनीकी संसाधनों की कमी बनी सबसे बड़ी बाधा

धाराओं में उलझे जांच अधिकारी; टैबलेट का इंटरनेट सुस्त, मोबाइल पर साक्ष्य जुटाने को मजबूर पुलिस

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

आज से दो साल पहले देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को संचालित करने वाले तीनों कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को बदलकर लागू किया गया। अब ये कानून क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाते हैं। कानूनों में बदलाव के समय कहा गया था कि इसका जोर दंड की बजाय न्याय पर होगा और इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी।

आज दो साल बाद स्थिति यह है कि जांच अधिकारी अपने पुराने प्रशिक्षण और बदली हुई धाराओं के विरोधाभासों में उलझ गए हैं। जांच और आरोप पत्र तक की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिस तरह के संसाधन चाहिए थे वह पुलिस को मुहैया नहीं हो पाए हैं, इसकी वजह से न्याय की रफ्तार अभी भी संतोषजनक नहीं हो पाई। नये कानूनों की असली ताकत इसके इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और डिजिटल वारंट में है। प्रदेश में यही इसका

सबसे कमजोर सिरा भी साबित हो रहा है। मौके पर वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल जब्ती जरूरी है,लेकिन थानों का तकनीकी ढांचा आज भी पुराना है।

डीसीपी हेडक्वाटर श्रृद्धा तिवारी ने बताया कि नए कानूनों के बाद जांच में तेजी के लिए शासन स्तर से मिले 800 टैबलेट्स में से 600 थानों को बांटे जा चुके हैं। इधर जांच अधिकारी कहते हैं कि उन टैबलेट में इंटरनेट बेहद सुस्त है। इसकी वजह से उनपर काम ही नहीं हो पाता। ऐसे में उन्हें अपने निजी मोबाइल फोन पर 'ई-साक्ष्य' एप चलाकर काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। कुछ जांच अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी सीडी और पेनड्राइव जैसे साधन तक स्वयं ही मंगवाने पड़ते हैं।

गवाहों को कैमरे के सामने लाना बड़ी चुनौती: डिजिटल युग में पुलिस के सामने सबसे संवेदनशील चुनौती गवाहों को कैमरे के सामने लाने की है। विशेषकर मादक पदार्थ तस्करी (एनडीपीएस) जैसे गंभीर मामलों में जहां जरा सी चूक साख पर सवाल उठाती है। सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक जीएस सिंह ने बताया कि नए कानून में गवाह को कैमरे के सामने बयान देने के लिए मनाना पुलिस के लिए एक बड़ा काम है। जबकि इस कानून का सबसे मजबूत पक्ष यह रहा है कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम वाट्सएप से डिजिटल वारंट तामील होने से गवाहों के मुकरने की गुंजाइश खत्म हुई है। साथ ही, अपराधियों की अनुपस्थिति में भी कोर्ट की सुनवाई जारी रहने के प्रावधान ने भगोड़ों को बड़ा झटका दिया है। हालांकि भोपाल जिला न्यायालय के अधिवक्ता सुरेश मालवीय और कमल रुचिरमानी जैसे कानूनी जानकारों का कहना जांच अधिकारियों की धाराओं को लेकर आने वाली दिक्कतें समय के साथ कम हो रही हैं। सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएन खान के अनुसार नए कानूनों के आने के बाद सुनवाई में तेजी आ गई है यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। अभी कुछ समय और गुजरने दीजिए, फिर इसके परिणाम स्पष्ट करेंगे। वारंट तामील होने के बाद भी सुनवाई के दिन गवाह कोर्ट में नहीं पहुंचता है, यह समस्या बनी हुई है। इससे न्याय में विलंब होता है।

आंकड़े भी दे रहे हैं गवाही

- एक जुलाई 2024 से अब तक 19,599 ई-एफआईआर दर्ज की गई, इनमें से सिर्फ़ 5,843 ही असल कायमी हुई।
- इस साल 4,290 ई-एफआईआर दर्ज की गईं। इनमें से सिर्फ़ 324 को एफआईआर में बदला गया।
- भोपाल में 55 में से सिर्फ पांच ई-एफआईआर में बदली।

सजावटी बनकर रह गया ई एफआईआर

रिटायर्ड डीएसपी आरके सिंह ने बताया कि नए कानूनों एक बड़ी सुविधा ई-एफआइआर की दी गई थी। इससे पीड़ित को थानों के चक्कर से मुक्ति मिलनी थी, लेकिन पुलिस का सिस्टम इसे वापस थाने की चौखट पर ही ले आया। नियम के मुताबिक ई-एफआईआर आवेदन के बाद शिकायतकर्ता को तीन दिन के भीतर भौतिक रूप से थाने पहुंचना होता है। जब पीड़ित को अंततः थाने ही जाना है, तो वह आनलाइन फार्म भरने का झंझट क्यों उठाए? यही कारण है कि लोग सीधे थाने जाकर ऑफलाइन एफआइआर कराना बेहतर समझ रहे हैं। इधर, थानों में तैनात स्टाफ आज भी ऑनलाइन आवेदनों को गंभीरता से नहीं लेता। वहीं पुलिस कमिश्नर, संजय कुमार पुलिस कर्मियों को नए कानूनों का समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनको हर संभव मदद दी जा रही है। आपराधिक केसों की कोर्ट में सुनवाई अब रफ्तार पकड़ रही है। ट्रेनिंग से उम्मीद है कि जांच अधिकारी नए प्रावधानों के साथ जल्द ही पूरी तरह सहज हो सकेंगे।

तीन माह का प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण सत्र अगस्त से

भोपाल। प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला भोपाल का आगामी नियमित लेखा प्रशिक्षण सत्र एक अगस्त से 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र तीन मूल प्रतियों में कार्यालय प्रमुख से अभिप्रमाणित कराकर लेखा प्रशिक्षण शाला में 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। जिन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण की हो या नियमानुसार छूट प्राप्त हो। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता एवं शासकीय कर्मचारी की परीवीक्षा अवधि पूरी होना भी अनिवार्य रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की जाति प्रमाण पत्र भी कार्यालय प्रमुख से सत्यापित कर संलग्न करना होगा। स्थानीय निकाय एवं अर्ध शासकीय संस्थाओं के लिपिक वर्गीय कर्मचारी जिनकी परीवीक्षा अवधि पूर्ण हो चुकी है वे भी प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण के समय कर्मचारियों का शुल्क 5000 का चालन जमा करना होगा।

करोंद क्षेत्र में कचरे का बढ़ता संकट, नगर निगम की लापरवाही से रहवासी परेशान

भोपाल. दोपहर मेट्रो। करोंद क्षेत्र में नगर निगम की लापरवाही के चलते कचरे की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। कॉलोनियों और मुख्य सड़कों के किनारे जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नियमित कचरा उठाव नहीं होने के कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। रहवासियों के अनुसार, कई स्थानों पर दिनों तक कचरा नहीं उठाया जाता, जिससे बदबू फैलने के साथ-साथ आवारा पशुओं का जमावड़ा भी लगा रहता है। बारिश के मौसम में यही कचरा नालियों में पहुंचकर जलभराव की समस्या को और बढ़ा देता है तथा मच्छरों और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कराया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया।

'सक्षम' का स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न

दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर वितरित

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से दिव्यांगजनों के क्षेत्र में कार्यरत संगठन 'सक्षम' का स्थापना दिवस समारोह 11 नंबर स्थित सक्षम कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुक्त दिव्यांगजन मध्य प्रदेश डॉ. अजय खेमरिया ने कहा कि सक्षम द्वारा देश के सात राज्यों में दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उपलब्ध कराने का अभियान संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 270 इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर का वितरण दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं भागीरथ प्रयास है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सक्षम के राज्य सचिव रविंद्र कोपरगांवकर ने की। उन्होंने कहा कि संगठन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी एकजुटता, सेवा भावना और सामूहिक कार्यशैली है। मंचासीन आशीष चटर्जी ने सक्षम की विभिन्न गतिविधियों एवं आगामी कार्ययोजना की जानकारी देते हुए संगठन की सेवा परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर वितरण के तृतीय चरण में किसी कारणवश वंचित रहे हितग्राहियों को भी व्हीलचेयर वितरित की गई।

कार्यक्रम का संचालन प्रदीप पांडरीपांडे ने किया, जबकि ए. पी. नायडू ने आभार व्यक्त किया। समारोह में रवि विभूते, देवेंद्र सिंह धाकड़, राज्य राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य विश्वजीत सरमंडल, प्रीति तांबे एवं राजेश शुक्ला सहित सक्षम के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे।

रंगमंच के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास

नाटक में दिखाया सआदत हसन मंटों का जीवन संघर्ष

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

सआदत हसन मंटो के जीवन, विचार और लेखकीय संघर्ष पर आधारित नाटक '42 साल, 8 महीने, 7 दिन' का मंचन किया गया। इस नाटक का मंचन मंटो के व्यक्तित्व और उनके लेखन की वैचारिक यात्रा को केंद्र में रखकर किया गया।

नाटक का निर्देशन घनश्याम तिवारी ने किया। नाटक में मंटो के निजी जीवन, उनकी पत्नी सफिया के साथ संवाद और एक लेखक के रूप में उनके आत्मसंघर्ष को प्रमुखता दी गई है। नाटक इस प्रश्न की पड़ताल करता है कि मंटो ने अपने समय की उन सच्चाइयों को लिखने का साहस क्यों किया, जिन्हें समाज स्वीकार करने से बचता रहा। उनके लेखन को लेकर उठे विवाद, अश्लीलता के आरोप, सामाजिक विरोध और इन सबके बीच एक लेखक की वैचारिक प्रतिबद्धता को संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। नाटक में मंटो के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को उनके वैचारिक संघर्ष के साथ जोड़ते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि उनका साहित्य उनके निजी अनुभवों और सामाजिक यथार्थ से किस प्रकार निर्मित हुआ। यह नाटक सिर्फ पात्र की जीवनी प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं है, बल्कि उनके विचारों, उनकी लेखकीय दृष्टि और सच के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रंगमंच के माध्यम से अभिव्यक्त करने का एक प्रयास है। नाटक में कलाकार शिखा जाट, शिवेन, रुद्रांश, सार्थक, राहुल, मुस्कान, साक्षी, सुहाना एवं शिखा ने प्रस्तुति दी।

सांसद, विधायक ने रेल अधिकारियों के साथ किया दौरा

सुविधाओं से लैस होगा संतनगर रेलवे स्टेशन, 37 करोड़ की विकास योजनाएं

संतनगर. दोपहर मेट्रो।

संत हिरदाराम नगर स्टेशन को आधुनिक से लैस करने लगभग 37 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं। जिसके चलते बुधवार को सांसद आलोक शर्मा और विधायक रामेश्वर शर्मा ने रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय, साफ-सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की। सांसद और विधायक ने अधिकारियों को स्टेशन परिसर में उच्च स्तरीय स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। यात्रियों के सुगम सफर के लिए यह घोषणा की गई कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म एक, दो और तीन पर नई लिफ्ट लगाई जाएंगी। इसके साथ ही, दिव्यांगजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक शौचालयों का निर्माण भी किया जाएगा।

कुटिया के पास बनेगा नया अंडरब्रिज: क्षेत्र की यातायात

व्यवस्था को सुगम बनाने और स्थानीय लोगों को रेलवे फाटक पर लगने वाले लंबे जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कुटिया के पास एक नए अंडरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं, फाटक रोड फ्लाईओवर निर्माण को लेकर विधायक ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि रेलवे के प्रोजेक्ट्स लंबी अवधि और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं, इसलिए इस फ्लाईओवर के निर्माण में थोड़ा समय लग सकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और मजबूती से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

पीपीपी मॉडल पर बनेंगे रेलवे गोदाम: विधायक रामेश्वर शर्मा ने संतनगर की व्यावसायिक महत्ता पर जोर देते हुए कहा कि यह क्षेत्र कपड़ा व्यापार का एक बड़ा हब है। व्यापारियों की सुविधा और स्थानीय कारोबार को गति देने के लिए स्टेशन परिसर की खाली जमीन पर पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत आधुनिक गोदाम विकसित करने की योजना है। इस संबंध में जल्द ही रेलवे अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर रूपरेखा तैयार की जाएगी।

जंक्शन के रूप में विकसित हो रहा है संतनगर स्टेशन: देशभर में तब्दील हो रहे 500 स्टेशनों के जीर्णोद्धार अभियान के तहत संत हिरदाराम नगर स्टेशन का भी चयन किया गया है। वर्तमान में स्टेशन पर प्रतीक्षालयों (वेटिंग रूम) की कमी को दूर करने के लिए तेजी से काम चल रहा है, और भविष्य की अन्य जरूरतों को भी चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन में ऐतिहासिक कदम

मध्यप्रदेशबनेगा देश का पहला जेंडर संवेदनशील आपदा प्रबंधन मॉडल राज्य

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

आपदा प्रबंधन प्रणाली को अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रभावी बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश ने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहल की है। राज्य अब देश का पहला जेंडर संवेदनशील आपदा प्रबंधन मॉडल लागू करने जा रहा है। इसके लिए होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा यूएन महिला संगठन के बीच 'प्रवाह चरण-2' के क्रियान्वयन हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे आपदा प्रबंधन में महिलाओं और संवेदनशील वर्गों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रवाह चरण-2 से मजबूत होगी आपदा प्रबंधन व्यवस्था-होमगार्ड मुख्यालय, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में यह सहमति पत्र होमगार्ड महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यूएन महिला संगठन की देश प्रतिनिधि शोको इशिकावा तथा उप पुलिस महानिरीक्षक अमित सांघी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और राहत एवं बचाव कार्यों में जेंडर संवेदनशील दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देना है।

महिलाओं और संवेदनशील वर्गों को मिलेगी प्राथमिकता

'प्रवाह चरण-2' के अंतर्गत आपदा प्रबंधन व्यवस्था में महिलाओं, बालिकाओं, वृद्धजनों और अन्य संवेदनशील वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को केंद्र में रखा जाएगा। राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों के दौरान उनकी गरिमा, सुरक्षा और सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही पहले चरण में तैयार जेंडर संवेदनशील आपदा जोखिम न्यूनीकरण मानक संचालन प्रक्रिया का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।

प्रशिक्षण और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान

इस मॉडल के अंतर्गत वर्तमान मानसून और अन्य आपदा स्थितियों में तैयार मानक संचालन प्रक्रिया के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके आधार पर भविष्य की रणनीति और कार्ययोजना को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। आपदा प्रबंधन दलों को महिलाओं की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि राहत कार्य अधिक मानवीय और प्रभावी हो सकें।

मेट्रो एंकर

आदित्य संस्कृति पत्रिका के विशेषांक का लोकार्पण

अपने नाम को सार्थक करते हैं डॉ.विकास दवे - रघुनंदन शर्मा

भोपाल. दोपहर मेट्रो।

'नाम का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, जैसे विकास नाम को सार्थक करते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉ.विकास दवे। वे एक अच्छे, संगठक, संपादक, साहित्यकार, मार्गदर्शक और सबको साथ लेकर चलने वाले अच्छे मित्र हैं।' यह उदगार हैं पूर्व सांसद और मानस भवन के संचालक रघुनंदन शर्मा के जो दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय सभागार में 'आदित्य संस्कृति' मासिक पत्रिका के साहित्यकार डॉ.विकास दवे विशेषांक का लोकार्पण करते हुए बोल रहे थे।

पत्रिका पर समीक्षात्मक टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार घनश्याम मैथिल अमृत ने कहा कि -' यह विशेषांक डॉ.विकास दवे की व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कई अनछुए पहलुओं को पाठकों के सामने प्रकट करता है। लघुकथा शोध केंद्र की निदेशक श्रीमती कांता रॉय ने

विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि डॉ दवे के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी राष्ट्र बोध की चेतना और सभी के प्रति समभाव की भावना अनुकरणीय है।' उर्दू अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद की निदेशक डॉ.नुसरत मेहदी ने कहा कि वे हम सबके मार्गदर्शक हैं। वे कभी किन्हीं परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते और सहज रहते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए वरिष्ठ साहित्यकार एवं निदेशक मुक्तिबोध सृजन पीठ ऋषि कुमार मिश्रा ने कहा कि शब्द ही हमारे मित्र शब्द ही हमारे शत्रु होते हैं। इसलिए शब्दों का हमें बड़े सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। आयोजन में डॉ.संजय सक्सेना, रामराव वामनकर, करुणा राजुरकर, कर्नल डॉ.गिरजेश सक्सेना, गोकुल सोनी, डॉ मोहन तिवारी आनंद, मनोज जैन मधुर, सुनील चतुर्वेदी, श्रीमती साधना गंगराड़े, श्रीमती सीमा शर्मा, हरिवल्लभ शर्मा, हरिओम श्रीवास्तव,जगदीश कौशल, डॉ.वीणा सिन्हा सहित अनेक साहित्यकार उपस्थित थे।

विशेषज्ञों की राय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

होमगार्ड महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने कहा कि यह पहल देश में पहली बार की गई है, जो आपदा प्रबंधन को नई दिशा देगी। वहीं यूएन महिला संगठन की प्रतिनिधि शोको इशिकावा ने कहा कि आपदाएं महिलाओं और बच्चों को अधिक प्रभावित करती हैं, इसलिए यह मॉडल अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय पहल बताया और मध्यप्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की।

ई-अटेंडेंस में लापरवाही: 1500 संकुल प्राचार्यों पर सस्पेंशन की लटकी तलवार

कटौती के बाद भी शिक्षकों का वेतन निकाला, डीईओ भी दायरे में

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश में ई-अटेंडेंस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्ती और बढ़ा दी है। अब 90 फीसदी से कम ई-अटेंडेंस वाले शिक्षकों का वेतन भुगतान कराने वाले संकुल प्राचार्यों पर निलंबन की कार्रवाई होगी। लोक शिक्षण आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि ऐसे प्राचार्यों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और संभागीय संयुक्त संचालक के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में करीब 1500 संकुल प्राचार्य हैं। एक संकुल के अंतर्गत औसतन 40 प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल आते हैं। ऐसे में नए आदेश का असर पूरे स्कूल शिक्षा तंत्र पर पड़ेगा।

लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार प्रदेश में फिलहाल करीब 95 फीसदी शिक्षक ही नियमित ई-अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं। यानी अभी भी कुछ शिक्षक निर्धारित मानकों के अनुरूप ई-अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। विभाग का कहना है कि ऐसे मामलों में वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू करना शासन के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा।

सस्पेंशन की कार्रवाई के निर्देश किए जारी- लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने कहा कि जिन शिक्षकों की ई-अटेंडेंस कम होने के कारण वेतन कटौती की गई है, उन्हें उपस्थिति के आधार पर ही वेतन मिलना है। इसके बावजूद कई संकुल प्राचार्यों ने वेतन कटौती के आदेश का पालन नहीं किया और वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसी वजह से उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि शैडो एरिया (जहां नेटवर्क की समस्या है) के मामलों में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को राहत देने का अधिकार है। यानी नेटवर्क संबंधी वास्तविक समस्याओं वाले मामलों में जिला स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है।

अफसर भी होंगे जवाबदेह

लोक शिक्षण आयुक्त ने आदेश में कहा है कि यदि संबंधित संकुल प्राचार्यों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित DEO और संयुक्त संचालक के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

शिक्षक संगठन लगातार कर रहे विरोध

शिक्षक संगठन लगातार ई-अटेंडेंस की 90त्न शर्त का विरोध कर रहे हैं। पिछले महीने कई संगठनों ने स्कूल शिक्षा मंत्री और अधिकारियों को ज्ञापन देकर इस शर्त में राहत देने की मांग की थी। हालांकि विभाग ने कोई छूट नहीं दी।

पहले वेतन कटौती, अब सस्पेंशन

विभाग ने पहले ई-अटेंडेंस नहीं लगाने वाले शिक्षकों के खिलाफ वेतन कटौती के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं होने पर अब कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया गया है। आदेश के मुताबिक, जिन संकुल प्राचार्यों ने कम ई-अटेंडेंस वाले शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की है, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी।

क्या है ई-अटेंडेंस सिस्टम?

- मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू की है।
- शिक्षक को स्कूल पहुंचकर मोबाइल ऐप के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होती है।
- उपस्थिति जीपीएस (लोकेशन) के आधार पर दर्ज होती है, ताकि शिक्षक स्कूल परिसर से ही अटेंडेंस लगा सकें।
- विभागीय पोर्टल पर सभी स्कूलों की उपस्थिति का डेटा रियल टाइम में मॉनिटर किया जाता है।
- लगातार ई-अटेंडेंस नहीं लगाने पर पहले वेतन कटौती का प्रावधान किया गया था, अब निलंबन की कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।
- विभाग ने 1 जुलाई 2026 से सभी शिक्षकों और शैक्षणिक अमले के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है।

बारिश बढ़ी, लेकिन लेकिन राहत देने वाली नहीं है बड़े बांधों की तस्वीर

एमपी के 27 जलाशयों में पिछले साल से कम पानी, इंदिरा सागर बांध सबसे ज्यादा खाली

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में मानसून अब रफ्तार पकड़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है और नदियों का जलस्तर भी बढ़ा है, लेकिन बड़े बांधों की तस्वीर अभी भी राहत देने वाली नहीं है। जल संसाधन विभाग की 30 जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 54 प्रमुख जलाशयों में औसत जलभराव 33.61 प्रतिशत दर्ज किया गया है। पिछले साल 30 जून को यह 32.02 प्रतिशत था। यानी एक साल में जलभराव में सिर्फ 1.59 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, आंकड़ों का दूसरा पहलू चिंता बढ़ाने वाला है। प्रदेश के 54 में से 27 जलाशयों में आज भी पिछले साल की तुलना में कम पानी है। यही वजह है कि लगातार बारिश के बावजूद इस बार प्रदेश के किसी भी बड़े बांध का एक भी गेट नहीं खोला गया है, जबकि नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है।

प्रदेश के सबसे बड़े इंदिरा सागर बांध की स्थिति सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रही है। यहां वर्तमान में 14.72 प्रतिशत जलभराव है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह करीब 24.5 प्रतिशत था। यानी करीब 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह बरगी में 12.45 प्रतिशत, तवा में 9.03 प्रतिशत, केरवा में 8.13 प्रतिशत, दहोद में 7.50 प्रतिशत, संजय सागर में 3.42 प्रतिशत, बाणसागर में 46.87 प्रतिशत और वाईगंगा (संजय सरोवर) में 9.21 प्रतिशत जलभराव दर्ज किया गया है। इन प्रमुख जलाशयों में अभी भी पानी का स्तर सामान्य से काफी कम है।

इन जलाशयों में मिली राहत

लगातार बारिश का असर कुछ जलाशयों में दिखाई देने लगा है। गांधीसागर (62.62 फीसदी), हरसी (53.96फीसदी), कुटनी (55.66त्न), मड़ीखेड़ा (64.77 फीसदी), राजघाट (79.75फीसदी), ओंकारेश्वर (39.28 फीसदी) और पहसारी (34 फीसदी) जैसे जलाशयों में पिछले साल की तुलना में बेहतर जलभराव दर्ज हुआ है। इससे उम्मीद है कि जुलाई में अच्छी बारिश जारी रही तो अन्य जलाशयों की स्थिति भी सुधर सकती है।

बारिश से नदियां चढ़ीं, लेकिन खतरे से दूर

पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई कैचमेंट क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। ओंकारेश्वर क्षेत्र में 179.40 मिमी, इंदिरा सागर में 146 मिमी, मोहनपुरा और कुंडलिया परियोजना क्षेत्र में 112.50-112.50 मिमी, पेंच डायवर्जन में 102.40 मिमी, तवा में 84.80 मिमी और वाईगंगा (संजय सरोवर) क्षेत्र में 83.50 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बारिश के बाद नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन, पार्वती और तामस समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सभी नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं और कहीं भी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है।

पिछले साल की तुलना में इस बार अलग तस्वीर

पिछले साल जून के आखिर तक लगातार हुई तेज बारिश से कई जलाशयों में तेजी से पानी बढ़ा था और बाद में कई बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ना पड़ा था। इसके उलट इस साल 30 जून तक लगातार बारिश के बावजूद जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किसी भी प्रमुख बांध का एक भी गेट नहीं खोला गया है। इससे साफ है कि जलाशयों में अभी अतिरिक्त पानी का दबाव नहीं बना है।

जुलाई की बारिश होगी निर्णायक

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि मानसून अब पूरे प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। यदि जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में लगातार अच्छी बारिश होती है तो बड़े जलाशयों में तेजी से जलभराव बढ़ेगा। इससे खरीफ फसलों की सिंचाई, पेयजल आपूर्ति के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा। वहीं यदि बारिश की रफ्तार धीमी रही तो कई बड़े जलाशयों में पानी की कमी बनी रह सकती है।

मप्र की हरित ऊर्जा क्रांति

सीएम ने 24 घंटे स्वच्छ बिजली देनेका किया ऐलान, दावा- प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बेहतर

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश अब स्वच्छ और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में 24 घंटे नवकरणीय (हरित) ऊर्जा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत का ऐलान करते हुए इसे ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने दिल्ली में आयोजित प्री-बिड मीटिंग को वर्चुअली संबोधित करते हुए दावा किया दावोस में किए गए निवेश और विकास संबंधी वादों को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है।

सीएम ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में चैबीसों घंटे स्वच्छ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उद्योगों, कृषि और आम उपभोक्ताओं को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह बात नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में आयोजित प्री-बिड बैठक को वर्चुअल संबोधित करते हुए कही, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना ने देश में सबसे कम सौर टैरिफ स्थापित कर भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। शाजापुर-नीमच सोलर पार्कों ने 2.14 रूपए प्रति यूनिट का प्रदेश में सबसे कम टैरिफ अर्जित किया। हाल ही में मुरैना की 4 घंटे की स्टोरेज प्लस परियोजना के लिए 2.70 रूपए प्रति यूनिट पर पीपीए हुआ, यह देश की सबसे प्रतिस्पर्धी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में से एक है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को पारदर्शी नीतियाँ, त्वरित निर्णय और उत्कृष्ट अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऊर्जा में आत्मनिर्भरता है हमारा लक्ष्य

सीएम ने कहा कि केवल परियोजनाएं स्थापित करना नहीं, बल्कि हरित ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना राज्य सरकार का उद्देश्य है। सीएम ने विश्वास जताया कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना और सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयास से 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा परियोजना भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास की दिशा में ऐतिहासिक सिद्ध होगी। नई दिल्ली की प्री-बिड मीटिंग में टाटा पॉवर, रिलायंस एनर्जी, टोरेंट पॉवर, जिंदल रिन्युएबल, एन.टी.पी.सी., अडानी ग्रीन्स, हिन्दुस्तान पॉवर, महिंद्रा सिस्टम आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

यूसीसी कानून से बाहर रह सकते हैं मतांतरित आदिवासी, विधानसभा में पेश होगा नया बिल

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक 20 जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें आदिवासियों के साथ-साथ मतांतरित आदिवासी भी कानून के दायरे से बाहर रखे जा सकते हैं। इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई वाली समिति को जन परामर्श में बड़ी संख्या में सुझाव मिले हैं। अधिकतर का पक्ष है कि जब आदिवासी मतांतरित हो गया तो फिर उसे आदिवासियों को मिलने वाले अधिकार व सुविधा से वंचित रखा जाना चाहिए। सैद्धांतिक तौर पर सभी इससे सहमत भी हैं लेकिन समिति कानूनी प्रविधान देख रही है।

जन परामर्श के दौरान भोपाल में पूर्व न्यायाधीश मोहन पी. तिवारी ने आदिवासियों को लेकर यह तर्क रखा था कि इनकी अपनी परंपराएं और व्यवस्थाएं हैं, इसलिए इन्हें कानून के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। जहां तक बात मत परिवर्तन करने वाले आदिवासियों की है तो वे मतांतरण के बाद आदिवासी तो रह नहीं गए।

अंतरजातीय विवाह और यूसीसी लागू करने पर जोर

वनवासी कल्याण आश्रम के एसएस कुमरे ने भी इस बात पर जोर दिया कि आदिवासी समाज की लड़की अगर दूसरी जाति में विवाह करती है तो उस पर यूसीसी लागू होना चाहिए। इसी तरह के अन्य सुझाव भी आए हैं। सूत्रों का कहना है कि समिति में इस विषयों को लेकर काफी विचार-विमर्श हुआ है। कानूनी पहलू भी देखे गए। दरअसल, संविधान के प्रविधान अनुसार एसटी वर्ग के लिए धर्म आधारित कोई रोक-टोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि आदिवासी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना ले, फिर भी वह कानूनी रूप से अपना एसटी का दर्जा और उससे जुड़े अधिकार बनाए रख सकता है।

आपदा प्रबंधन में जेंडर संवेदनशीलता की दिशा में मध्यप्रदेश ने रचा इतिहास

भोपाल। आपदा प्रबंधन को अधिक समावेशी, संवेदनशील एवं प्रभावी बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए देश का पहला जेंडर रिस्पॉन्सिव आपदा प्रबंधन मॉडल विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसी क्रम में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा यूएन वूमेन के मध्यप्रवाह फेज-2कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु होमगार्ड मुख्यालय, भोपाल में सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू होमगार्ड महानिदेशकश्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तवकी गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ।

विकास के दावों की पोल खोलती यह खरगोन की तस्वीर

नदी में नहीं पुल, जोखिम में ग्रामीणों की जान बच्चों को कंधों में बैठाकर पहुंचा रहे हैं स्कूल

खरगोन, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदश के कई जिलों में मानूसन ने दस्तक देने के साथ ही जोरदार बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। बारिश के बीच इन जिलों से ऐसी तस्वीर भी सामने आने लगी हैं सरकार की विकास के दावों की पोल भी खोल रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीकर खरगोन जिले से आई हैं, जहां पुल न होने से परिजनों को स्कूली बच्चों को कंधों और हाथ पकड़कर उफनती नदी को पार कराना पड़ रहा है। भगवानपुरा तहसील के वन ग्राम पीपलझोपा के राजमोहली से सामने आए वीडियो ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की पोल खोल दी है। वीडियो में स्कूली बच्चों को उनके परिजन हाथ पकड़कर कुंदा नदी पार कराते दिखाई दे रहे हैं, ताकि वे स्कूल पहुंच सकें। लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, लेकिन पुल के अभाव में ग्रामीणों के पास यही एकमात्र रास्ता बचता है। हर साल मानसून के दौरान यही हालात बनते हैं और कई दिनों तक गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से कट जाता है।

कमजोर पड़ते सहकारी आंदोलन को धार देगी कांग्रेस

मप्र में भंवर सिंह शेखावत को सौंपी सहकारिता की कमान

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रदेश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस अभियान चलाएगी। इसके लिए समिति बनाई गई है। वहीं, प्रदेश कांग्रेस के सहकारिता विभाग का अध्यक्ष भंवर सिंह शेखावत को बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह, विधायक भंवर सिंह शेखावत को शामिल किया है। इसका समन्वय संयोजक चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी को बनाया है।

सहकारिता के विशेषज्ञों से साधेंगे संपर्क- समिति की पहली बैठक मंगलवार को पहली बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में की गई। इसमें सहकारी आंदोलन के कमजोर पड़ने और इसे फिर सशक्त बनाने की दृष्टि से निर्णय लिया गया कि संचालन समिति प्रदेशभर के सहकारी आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों, विशेषज्ञों एवं कार्यकर्ताओं से संपर्क कर एक विस्तृत बैठक करेगी। इसमें सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करने, किसानों के हितों की रक्षा करने तथा प्रदेश में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बैठक में ही सर्वसम्मति से भंवर सिंह शेखावत को मध्य प्रदेश कांग्रेस सहकारिता विभाग के अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया।

प्रहलाद पटेल ने दिए नियमों को सरल और हितकारी बनाने के निर्देश

श्रमिकों के लिए आसान होंगे नए श्रम कानून, प्रवासी मजदूरों को भी राहत

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश सरकार नई श्रम संहिताओं के राज्य नियमों को अधिक श्रमिक-केंद्रित और व्यवहारिक बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विभागीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि राष्ट्रीय फ्लोर वेज और न्यूनतम मजदूरी तय करते समय कृषि श्रमिकों की कार्यकुशलता, बाजार की वास्तविक स्थिति तथा विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित मजदूरी दरों का गहन अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि मजदूरी निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह यथार्थपरक और श्रमिक हितों के अनुरूप होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नई श्रम संहिताओं का उद्देश्य केवल कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि श्रमिकों को अधिक सामाजिक सुरक्षा और नियोक्ताओं के साथ बेहतर समन्वय उपलब्ध कराना है। मंत्री ने श्रमिक कल्याण मंडलों में अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने, असंगठित श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाने तथा संबल योजना का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने बीमा न्यायालय की कार्यप्रणाली, अर्द्धन्यायिक व्यवस्था और श्रमिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों को भी अधिक स्पष्ट और संवेदनशील बनाने पर जोर दिया।

पत्रकारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान

मंत्री पटेल ने श्रमजीवी पत्रकारों से जुड़े नियमों पर चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी नए प्रावधान को अंतिम रूप देने से पहले पत्रकार संगठनों और उनके प्रतिनिधियों से व्यापक संवाद किया जाए। वहीं, अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए आधुनिक डिजिटल पोर्टल विकसित करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रवासी श्रमिकों का सटीक डेटाबेस तैयार होगा और जरूरत पड़ने पर उन्हें समय पर सहायता व सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। उन्होंने पंचायत सचिवों और नगरीय निकायों के वार्ड स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करने के निर्देश दिए।

तकनीक आधारित होगी नई व्यवस्था

बैठक में श्रमिक दुर्घटनाओं की त्वरित सूचना और सहायता के लिए सक्रिय पोर्टल एवं टोल-फ्री हेल्पलाइन विकसित करने, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमापूर्ण सुविधाएं सुनिश्चित करने तथा निरीक्षक प्रणाली की जगह सुविधा प्रदाता (फैसिलिटेटर) आधारित व्यवस्था लागू करने पर भी चर्चा हुई। विभाग के सचिव रघुराज राजेन्द्रन ने बताया कि 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर चार नई श्रम संहिताएं तैयार की गई हैं।

आसमान ने खोली आंखे

आधुनिक युद्ध की दुनिया में जीत केवल ताकतवर हथियारों या तेज लड़ाकू विमानों से तय नहीं होती। आज युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है- सूचना। जो पक्ष दुश्मन को पहले देख लेता है, उसकी गतिविधियों को पहले समझ लेता है और समय रहते सही निर्णय ले लेता है, वही बढ़त हासिल करता है। ऐसे समय में भारत की स्वदेशी 'नेत्र' एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (एईडब्ल्यू एंड सी) प्रणाली को अंतिम परिचालन मंजूरी मिलना केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि देश की तकनीकी और रणनीतिक क्षमता का महत्वपूर्ण प्रमाण है। 'नेत्र' को अक्सर भारत की 'आसमानी आंख' कहा जाता है। यह एक उड़ता हुआ रडार स्टेशन है, जो हजारों फीट की ऊंचाई से विशाल क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। यह दुश्मन के विमानों, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों का समय रहते पता लगाकर उनकी जानकारी लड़ाकू विमानों और कमान केंद्रों तक पहुंचाता है। इस तरह यह केवल निगरानी ही नहीं करता, बल्कि पूरे युद्ध प्रबंधन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाता है। इस उपलब्धि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसकी जड़ें कारगिल युद्ध के अनुभवों में हैं। 1999 के संघर्ष ने भारत को यह एहसास कराया था कि भविष्य के युद्धों में केवल साहस और सैन्य शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। बेहतर निगरानी, त्वरित सूचना और समन्वित कमान प्रणाली भी उतनी ही आवश्यक होगी। 'नेत्र' उसी सोच का परिणाम है, जिसे विकसित करने में वर्षों का शोध, परीक्षण और धैर्य लगा। लेकिन यह कहानी केवल एक रक्षा प्रणाली की नहीं है। यह भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी भी है। लंबे समय तक उन्नत सैन्य तकनीकों के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहने वाला भारत अब उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो रहा है, जो ऐसी जटिल प्रणालियों का विकास स्वयं कर सकते हैं। यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। आज जब भारत के सामने दो परमाणु-संपन्न और तेजी से आधुनिक होती वायु सेनाओं वाले पड़ोसी मौजूद हैं, तब स्वदेशी निगरानी क्षमता का महत्व और बढ़ जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक लाभ का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता और दीर्घकालिक सुरक्षा का भी प्रश्न है। 'नेत्र' की सफलता यह संदेश देती है कि आधुनिक युग में शक्ति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि ज्ञान, तकनीक और दूरदृष्टि से निर्मित होती है।

ड्रग्स माफिया पर तीन स्तरीय वार पहचान, प्रहार और पूर्ण सफाया

डॉ. मयंक चतुर्वेदी
स्तंभकार

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार हो सकता है, जब देश की युवा शक्ति सुरक्षित, स्वस्थ और उत्पादक बनी रहे। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अब नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल कानून-व्यवस्था का विषय न मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा का अभियान बना दिया है। इसी सोच के साथ जारी 'मादक पदार्थ नियंत्रण विज़न डॉक्यूमेंट 2026-2029' यह संकेत देता है कि अब कार्रवाई का लक्ष्य पूरे नार्को इकोसिस्टम को जड़ से खत्म करना है।

पिछले कुछ वर्षों में यह साफ हुआ है कि ड्रग्स कारोबार के तार आतंकवाद, हवाला, संगठित अपराध, सीमा पार तस्करी और डिजिटल अपराधों से जुड़ चुके हैं। ऐसे में यदि कार्रवाई केवल छोटे तस्करों तक सीमित रहे तो समस्या का समाधान संभव नहीं है। सरकार ने इसी कमजोरी को पहचानते हुए अब 'डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय' का नया मंत्र दिया है। मोदी सरकार की यह कार्यप्रणाली बताती है कि पहले पूरे नेटवर्क की पहचान होगी, फिर उसकी सप्लाई चेन और वित्तीय तंत्र को तोड़ा जाएगा और अंततः पूरे कार्टेल का स्थायी खात्मा किया जाएगा।

इस नई नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें अपराधियों के साथ-साथ उनके आर्थिक ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। वस्तुतः अब केवल मादक पदार्थ जब्त कर लेना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। हवाला नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले लेन-देन, डार्कनेट पर संचालित कारोबार, बैंक खातों और अवैध संपत्तियों तक कार्रवाई का दायरा बढ़ाया गया है। स्पष्ट है कि सरकार ड्रग्स माफिया की आर्थिक रीढ़ तोड़कर इस कारोबार को असंभव बनाना चाहती है। आज ड्रग्स तस्करी का स्वरूप भी तेजी से बदल रहा है। ड्रोन के माध्यम से सीमा पार खेप पहुंचाना, समुद्री मार्गों का इस्तेमाल, कंटेनर तस्करी, ऑनलाइन नेटवर्क और डार्क वेब के जरिए अवैध व्यापार जैसी चुनौतियां पारंपरिक पुलिस व्यवस्था से नहीं सुलझ सकतीं, इसलिए विज़न डॉक्यूमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, तकनीकी खुफिया तंत्र, अपराध मानचित्रण और आधुनिक निगरानी प्रणाली को विशेष महत्व दिया गया है। यह बदलाव बताता है कि सरकार अब अपराधियों से एक कदम आगे रहने की रणनीति पर काम कर रही है।

इस अभियान की एक और उल्लेखनीय विशेषता ध्यान में आई है, वह यह है कि इसमें केवल सख्ती नहीं, संवेदनशीलता भी दिखाई देती है। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट भी कर दिया है, ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरह कठोर होगी, किंतु नशे की लत के शिकार युवाओं को अपराधी न मानकर उन्हें पीड़ित मनकर उनके पुनर्वास पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। यह संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक भी है क्योंकि नशे के खिलाफ स्थायी सफलता गिरफ्तारी से अधिक समाज को नशामुक्त बनाने से मिलेगी। कहना होगा कि सरकार की चार स्तंभों वाली कार्ययोजना इसी व्यापक सोच को दर्शाती है। प्रभावी प्रवर्तन, सिंथेटिक ड्रग्स और रसायनों पर नियंत्रण, नशे की मांग कम करना तथा पुनर्वास और संस्थागत क्षमता निर्माण, इन सभी पहलुओं को समान महत्व दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार समस्या के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष पर भी काम करना चाहती है।

राज्यों की भूमिका को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई केवल केंद्र सरकार नहीं जीत सकती। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को अधिक संसाधन, एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, मजबूत चार्जशीट और जवाबदेह व्यवस्था पर जोर बताता है कि अब परिणाम आधारित कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि राज्यों में यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो ड्रग्स नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाए रखना संभव होगा। विशेष एनडीपीएस अदालतों के गठन पर दिया गया जोर भी स्वागतयोग्य है। अक्सर वर्षों तक मुकदमे लंबित रहने से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। यदि जांच के साथ त्वरित सुनवाई और शीघ्र सजा सुनिश्चित होती है तो इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी व्यापक होगा और ड्रग्स कारोबार में शामिल लोगों के लिए कानून का डर बढ़ेगा।

सरकार ने सीमाओं से लेकर गांवों तक निगरानी मजबूत करने की जो योजना बनाई है, वह भी महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती गांव, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और संवेदनशील जिलों में तकनीकी निगरानी तथा कम्युनिटी पुलिसिंग का विस्तार इस बात का संकेत है कि अब तस्करी के हर संभावित मार्ग पर नजर रखी जाएगी। साथ ही अवैध अफीम और अन्य मादक फसलों की खेती के खिलाफ बढ़ती कार्रवाई यह दर्शाती है कि सरकार उत्पादन के स्रोत पर भी समान सख्ती बरत रही है। ड्रग्स के खिलाफ समाज की भागीदारी को अभियान का आधार बनाना भी दूरदर्शी कदम है। माता-पिता, शिक्षक, शिक्षण संस्थान, युवा संगठन और सामाजिक संस्थाएं यदि इस लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो नशे की मांग स्वतः घटेगी। आखिर किसी भी अवैध कारोबार का सबसे बड़ा आधार उसकी मांग होती है। जब समाज ही नशे के प्रति जागरूक होगा तो तस्करी के नेटवर्क भी कमजोर पड़ेंगे।

निःस्संदेह, नशामुक्त भारत का लक्ष्य सिर्फ सरकारी योजनाओं के भरोसे हासिल नहीं हो सकता है, इसके लिए कानून, तकनीक, न्याय व्यवस्था, सामाजिक जागरूकता और जनसहभागिता से लेकर वे तमाम उपाय एक साथ हर मोर्चे पर करने होंगे, जो इसे रोकने के लिए आवश्यक हैं। 'डिटेक्ट, डिसरप्ट और डिस्ट्रॉय' की नई रणनीति इसी समग्र सोच का परिचायक है। यदि इस रोडमैप को पूरी प्रतिबद्धता और समन्वय के साथ लागू किया गया तो आने वाले वर्षों में भारत उम्मीद करेंगे कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ निर्णायक बढ़त हासिल करेगा, तभी हम सही मायनों में विकसित भारत के संकल्प को भी एक मजबूत सामाजिक आधार प्रदान कर पाएंगे।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

आस्था के केंद्र राम मंदिर की अमानत में खयानत, बड़ा सवाल... आगे की राह क्या हो ?

गिरीश्वर मिश्र
महात्मा गाँधी हिंदी विवि के पूर्व कुलपति

पुण्य नगरी अयोध्या में प्रभु श्रीराम के नवनिर्मित भव्य मंदिर में चढ़ावे और दान के हिसाब-किताब की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और व्यवस्था में कई खामियाँ नजर आ रही हैं। पवित्र सरयू नदी के तट स्थित यह अवधपुरी विगत दिनों से कई तरह के आरोप-प्रत्यारोप के बीच चर्चा में बनी हुई है। हम सबको याद है कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ था। विगत वर्षों में अयोध्या धाम के जीर्णोद्धार के बाद वहाँ देश के विभिन्न भागों से अपार संख्या में श्रद्धालुओं और भक्तों का आना-जाना शुरू हुआ और वहाँ लोगों का जमावड़ा लगातार बना रहता है। विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की इतनी संख्या में आना कीर्तिमान बना रहा है। इन सबके बीच अयोध्या का परिवेश निश्चित ही बदल रहा है और वहाँ की व्यवस्था में सुधार भी हो रहा है। आज पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर आयोजनों के साथ अयोध्या के पूरे क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक पारिस्थितिकी नया रूप ले रही है। ऐसे में पौराणिक नगरी अयोध्या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर नई पहचान बनाने को उद्यत है।

यह क्षेत्र निश्चित ही अब देश में आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के कार्यकलापों के अभिनव केंद्र के रूप में उभर रहा है। ऐसे में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि राममंदिर की देखरेख की प्रबंध व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। उसे लेकर ताजा घटनाक्रम रामभक्तों के लिए चिंताजनक हो रहे हैं। साथ ही उसे लेकर सियासी पारा भी गर्म हो रहा है। राममंदिर की व्यवस्था को लेकर लगा आरोप न केवल बेहद संगीन है बल्कि सबके लिए शर्मनाक भी। आरोप में कहा गया है कि मंदिर में आने वाले भक्तों द्वारा जो चढ़ावा प्रभु के श्रीचरणों में श्रद्धा भाव से अर्पित होता रहा है, उसे संभालने वाले ट्रस्ट द्वारा नियुक्त कर्मी आवश्यक ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे थे। वे चढ़ावे को न सुरक्षित रख पा रहे थे बल्कि उसमें अपनी मर्जी से लगातार हेराफेरी भी करते आ रहे थे। इन लोगों पर चढ़ावे में आने वाली एकत्रित धनराशि को व्यवस्थित करने यानी गिनने, रखने आदि के बीच मौजूद राशि में से कुछ राशि गायब कर देने का आरोप भी लगा है। चढ़ावे में मिली नगदी की गिनती और उसकी निगरानी व्यवस्था बहुत लचर थी और उसमें खामियां पाई गईं। दान आने के बाद जो धनराशि की गिनती करते थे उनके मंदिर प्रवेश और मंदिर से बाहर जाने पर कोई सघन निगरानी की व्यवस्था नहीं थी।

इन लोगों के इस काम के लिए पात्रता और चयन प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। साथ ही भक्तों द्वारा भगवान की सेवा में अर्पित सोने-चाँदी के आभूषण आदि तथा अन्य बहुमूल्य भेंट को भी गायब करने के आरोप लग रहे हैं। बेईमानी और घूसखोरी के किस्से कई पुलिस और कोर्ट-कचहरी जैसे सरकारी जगहों और महकमों में चलते आ रहे हैं। आम आदमी उनसे सुपरिचित हैं। परंतु देवस्थान बड़े पवित्र होते हैं, उनकी मर्यादा होती है और बहुत से लोग लाचार होकर ईश्वर की शरण में आते हैं। वे अपना प्रणाम निवेदित कराते हैं और यथाशक्ति दान-दक्षिणा अर्पित करते हैं। उनकी आस्था और श्रद्धा के साथ इस तरह से खिलवाड़ अमानवीय अपराध है। राममंदिर के बही-खाते और लेनदेन की पारदर्शिता मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था और सरकार दोनों की साख को सुरक्षित रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

आश्चर्य की बात यह है कि अयोध्या के राममंदिर परिसर से जुड़ी इस तरह की खबर पहले भी यदाकदा आती थी परंतु उस पर किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया और सारी व्यवस्था ज्यों-कि-त्यों चलती रही। ट्रस्ट के प्रबंधन पर सबका भरोसा था पर वास्तविकता कुछ और थी। जो मानक पद्धति या एसओपी तय थी, उसका पालन नहीं हो रहा था, न ही उसकी उपयुक्तता सुनिश्चित की गई थी। जो लोग काम पर लगे थे वे प्रशिक्षित न होकर कुछ लोगों की संस्तुति पर लगे थे। वहाँ प्रचलित व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया गया और सबकुछ ज्यों-का-त्यों पूर्ववत चलता रहा। तूल पड़ने पर इस मामले में करोड़ों का घोटाला करने के आरोपों में प्रथम दृष्टया सच्चाई भांप कर तत्काल कानूनी कारवाई करने और अपराधियों को दंडित करने के लिए राज्य सरकार ने जाँच बिठाने का निर्णय लिया। इस सिलसिले में उच्चस्तरीय एसआईटी गठित की गई है और उसकी आरंभिक जांच रिपोर्ट अब मिल चुकी है। एसआईटी ने मंदिर से जुड़े कर्मियों से बातचीत की, जानकारी एकत्र की और अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को दी है। रिपोर्ट लेकर सरकार ने प्राप्त तथ्यों का संज्ञान लेकर कानून के आलोक में चढ़ावे की व्यवस्था से सीधे-सीधे जुड़े आठ मन्दिर कर्मियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर कर आगे की क़ानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। इन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

भारत में अनेक मंदिर और देव स्थान हैं जहाँ पहुंचने के लिए भक्त जनों का ताँता लगा रहता है। तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, जगन्नाथ पुरी, बदरी केदार धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकाल मंदिर उज्जैन, वैद्यनाथधाम, शिरडी साईं स्थान आदि अनेक स्थल भक्तजनों को निरंतर आकर्षित करते हैं। ऐसे स्थलों पर चढ़ावे की प्रचुर मात्रा की व्यवस्था, रखरखाव और सदुपयोग के लिए व्यापक विचार-विमर्श कर नीति बनाना जरूरी है। अच्छा हो आराधना स्थली की आवश्यकताओं को पूरा कर विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं को सुधारने में चढ़ावे की धनराशि का उपयोग किया जाय। कुछ स्थलों पर ऐसा हो भी रहा है किंतु अभी भी चढ़ावे की धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अपडेट

सनलाइट थेरेपी से हार्मोनल बैलेंस, थायरॉइड ठीक करने में भी मिलती है मदद

आधुनिक जीवनशैली में अधिकतर व्यक्ति धूप में बैठने से बचते हैं। सूर्य की यूवी किरणों से त्वचा को बचाने के लिए व्यक्ति सूर्य की रोशनी में जाना या रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन, सूर्य की रोशनी में न रहने की वजह से लोगों को विटामिन डी की कमी होने का जोखिम बढ़ जाता है। जो थायरॉइड फंक्शन, टेस्टोस्टेरोन लेवल, महिला प्रजनन हार्मोन्स और मूड को प्रभावित करने वाले हार्मोन सेरोटोनिन पर असर डाल सकती है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि धूप केवल शरीर को गर्माहट ही नहीं देती, बल्कि यह हार्मोन उत्पादन, मानसिक स्वास्थ्य और मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने वाली कई जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है।

जब स्किन सनलाइट थेरेपी के जरिए सूरज की UVB किरणों के संपर्क में आती है, तो शरीर विटामिन D बनाता है। यह विटामिन वास्तव में एक हार्मोन की तरह कार्य करता है और शरीर के कई हार्मोनल कार्यों को प्रभावित करता है। एनसीबीआई की स्टडी के अनुसार विटामिन D शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम के कई हिस्सों पर प्रभाव डालता है और हार्मोनल स्वास्थ्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन D इंसुलिन, पैराथायरॉइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और इम्यून सिस्टम से जुड़े कई कार्यों में योगदान देता है। इसकी कमी हार्मोनल असंतुलन, थकान, कमजोर इम्युनिटी और मूड संबंधी समस्याओं से जुड़ी हुई पाई गई है।

एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों में विटामिन डी का स्तर बेहतर होता है, उनमें टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। धूप शरीर में विटामिन डी उत्पादन को बढ़ाती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन स्वास्थ्य को सपोर्ट मिल सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि विटामिन डी का स्तर और टेस्टोस्टेरोन आपस में जुड़े हुए हैं। टेस्टोस्टेरोन व्यक्ति की नींद, उम्र, वजन और जीवनशैली से भी प्रभावित होता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म और हड्डियों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्टडी के अनुसार विटामिन डी महिला प्रजनन प्रणाली में मौजूद रिसेप्टर्स के माध्यम से कई हार्मोनल प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है।

सनलाइट थेरेपी केवल विटामिन डी प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नियमित धूप लेने से विटामिन डी स्तर बेहतर हो सकता है, जो थायरॉइड स्वास्थ्य, टेस्टोस्टेरोन, महिला हार्मोन्स और सेरोटोनिन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स को प्रभावित करता है।

निशाना

ये कैसी खुद्दारी पक्की..!

मनोज साहू 'निडर'

चोर-चोर में यारी पक्की।
झूठों की सरदारी पक्की।
जिसके सिर इल्ज़ाम बड़े हों
उनकी दावेदारी पक्की।
गीदड़ के संग शेर जो बैठें
फितरत में मक्कारी पक्की।
कोई बने सरकार हमें क्या
अपनी हिस्सेदारी पक्की।
बहती गंगा हाथ धुले जो
उसकी गठरी भारी पक्की।
मौका मिलते ही बदलेंगे
जिनकी नातेदारी पक्की।
दान हड़प कर चंपत होना,
कैसी ये खुद्दारी पक्की।

नॉलेज

करोड़ों सालों से जिंदा रही है पैंगोलिन, इंसानी लालच ने 10 साल में कर दिया बर्बाद!

धरती पर कई ऐसे जीव हैं जो लाखों-करोड़ों साल से बिना बदले जीवित है। इन्हें प्रकृति ने इतनी मजबूती दी है कि बड़े-बड़े शिकारी भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। लेकिन इंसान का लालच इन प्राचीन जीवों को भी बर्बाद कर रहा है। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी है पैंगोलिन की। यह अनोखा जीव पिछले 8 करोड़ साल से धरती पर राज कर रहा था, लेकिन इंसानों ने सिर्फ 10 साल में इसे विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया है। पैंगोलिन को 'स्केली एंटईटर' भी कहा जाता है। इसका पूरा शरीर मजबूत शल्कों (scales) से ढका होता है जो केराटिन से बने होते हैं। खतरे के समय यह गोले का रूप धारण कर लेता है। यही कारण है कि शेर, चीता, भालू या हाथी जैसे जानवर भी इसे आसानी से नहीं खा पाते। लाखों सालों से यह रणनीति इनकी सुरक्षा करती रही। लेकिन इंसान के सामने यह रक्षा बेकार साबित हुई।

चीन, वियतनाम और अन्य एशियाई देशों में पैंगोलिन की स्केल्स को पारंपरिक दवा में इस्तेमाल किया जाता है। इसके मांस को स्वादिष्ट माना जाता है। नतीजतन, दुनिया भर में पैंगोलिन सबसे ज्यादा तस्करी वाला जानवर बन गया है। आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में हजारों पैंगोलिन पकड़े गए लेकिन इससे कहीं ज्यादा तस्करी हो रही है।

तस्करी का भयानक आंकड़ा: विश्व व्यापार में हर साल हजारों टन पैंगोलिन स्केल्स बरामद होती हैं। अफ्रीका से एशिया की ओर तस्करी का नेटवर्क बहुत सक्रिय है। एक रिपोर्ट के अनुसार, 2010 के बाद से पैंगोलिन की आबादी में 80% तक की गिरावट दर्ज की गई है। एशिया में कुछ प्रजातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। अफ्रीकी प्रजातियां भी तेजी से खत्म हो रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पैंगोलिन 80 मिलियन साल पुरानी प्रजाति है। डायनासोर काल से भी पहले यह धरती पर था। लेकिन इंसानी गतिविधियां, जंगलों की कटाई और अवैध शिकार ने इसे मिटा दिया।

पैंगोलिन पर्यावरण संतुलन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये चींटी और दीमक खाकर फसल की सुरक्षा करते हैं। अगर पैंगोलिन खत्म हो गए तो कीटों की संख्या बढ़ेगी जो कृषि के लिए नुकसानदायक साबित होगी। भारत में भी पैंगोलिन पाए जाते हैं। उत्तर-पूर्वी राज्य, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य इलाकों में इनकी मौजूदगी है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत पैंगोलिन को उच्चतम सुरक्षा दी गई है लेकिन तस्करी रुक नहीं रही है।

इनोवेशन

खारे पानी से बनेगी बिजली, 'सूरज' का ईंधन निकालने वाली मशीन हो रही तैयार

कनाडा की 'नेक्स्ट हाइड्रोजन' और 'फ्यूजन फ्यूल साइकिल्स' नाम की दो कंपनियां मिलकर एक नई मशीन बना रही हैं। यह मशीन भारी पानी से 'ट्रिटियम' नाम का ईंधन अलग करेगी। यही वो ईंधन है जिससे सूरज अपनी रोशनी और गर्मी से लगातार बनाता है। 31 करोड़ की यह अनोखी मशीन पुरानी मशीनों से तीन गुना छोटी है, जो बिना प्रदूषण असीमित बिजली देगी। बिना किसी प्रदूषण के असीमित बिजली बनाना लगभग हर देश के लिए किसी सपने के जैसा है। वैज्ञानिक सालों से ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं, जो ठीक वैसे ही बिजली बनाएगी जैसे कि सूरज अपनी रौशनी और गर्मी बनाता है। इसे फ्यूजन एनर्जी कहा जाता है। इस बिजली को बनाने के लिए खास तरह के ईंधन ट्रिटियम की जरूरत पड़ती है।

सूरज जैसी बिजली बनाने के लिए ट्रिटियम नाम के ईंधन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हाइड्रोजन कंपनी जिस मशीन पर काम कर रही है वह भारी पानी यानी कि खारे पानी से इस कीमती ईंधन को अलग करेगी। फ्यूजन फ्यूल साइकिल्स नाम की दूसरी कंपनी इस मशीन को अपने सिस्टम में फिट करेगी। इस मशीन की खासियत है कि इसमें गैस और पानी को अलग-अलग करने का सिस्टम मशीन में ही लगा है। इससे ईंधन के लीक होने या उसमें किसी कचरे के मिलने की संभावना खत्म हो जाती है। इसकी वजह से यह पूरी मशीन बेहद भरोसेमंद साबित होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार मशीन की सबसे बड़ी खासियत है कि यह पारंपरिक मशीनों से काफी छोटी होगी। इससे पहले की मशीनों में बड़े-बड़े ड्रम और पाइप भी लगाने पड़ते थे लेकिन नई मशीन में इसकी जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें सबकुछ अंदर ही फिट होगा। इससे बिजली प्लांट लगाने वाली कंपनियों को बड़ा फायदा होगा, जो कि छनकर आम लोगों को भी मिल पाएगा। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी वजह से बिजली का प्लांट लगाने वाली कंपनियों को ईंधन बनाने के तामझाम से मुक्ति मिलेगी। इससे कंपनियां अपना ध्यान पूरी तरह से बिजली बनाने वाले मेन रिएक्टर को बेहतर बनाने पर लगा सकेंगी। इसकी खासियत है कि यह मशीन करीब 80 हजार घंटे तक बिना रुके चल सकती है, जो इस इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। खारे पानी ने निकले ईंधन से बनने वाली फ्यूजन बिजली जब बाजार में आएगी, तो यह कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा साबित होगी। इससे लोगों को महंगी बिजली से राहत मिल सकेगी। यह तकनीक सूरज या पवन ऊर्जा की तरह मौसम पर निर्भर नहीं होगी। यह पूरे साल लगातार बिजली बना सकेगी। यह शुद्ध ऊर्जा का स्त्रोत बनेगी और कोयला और गैस न जलने के कारण हवा में जहरीला धुआं घुलना बंद हो जाएगा। इससे भी लोगों को ही साफ पर्यावरण मिलेगा। पुरानी तकनीक की तरह इसमें ब्लास्ट होने या खतरनाक रेडियोएक्टिव कचरा हफ्तों तक पड़े रहने का कोई डर नहीं होगा।

न्यूज विंडो

महामना एक्सप्रेस का समय बदलने के विरोध में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

गंज बासौदा । महामना एक्सप्रेस के प्रस्तावित समय परिवर्तन को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने स्टेशन प्रबंधक से मुलाकात कर रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि महामना एक्सप्रेस का वर्तमान समय यथावत रखा जाए। यदि परिचालन संबंधी कारणों से समय परिवर्तन आवश्यक हो, तो यात्रियों की सुविधा के लिए उसी समयावधि में एक नई ट्रेन का संचालन किया जाए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नितिन दुबे ने बताया कि गंज बासौदा, विदिशा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री इस ट्रेन से आवागमन करते हैं। विशेष रूप से भोपाल, विदिशा और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु तालबेहट स्थित बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए इसी ट्रेन का उपयोग करते हैं। वर्तमान समय-सारिणी के कारण श्रद्धालु एक ही दिन में दर्शन कर वापस लौट आते हैं, जबकि समय परिवर्तन होने पर उन्हें अतिरिक्त समय, खर्च और असुविधा का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन में रेल मंत्री से जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित समय परिवर्तन पर पुनर्विचार करने तथा यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नितिन दुबे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विकास शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुनील बाबू पिंगले, राजकुमार सेन, प्रशांत नायक एवं गुड्डू नायक सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली चप्पल बेचने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई

जबलपुर। जबलपुर में ब्रांडेड कंपनी पूमा के नाम पर नकली चप्पल बेचने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी के नाम और डिजाइन की हूबहू कॉपी कर बाजार में बेची जा रही नकली स्लाइडर्स चप्पलों को पुलिस ने दो होलसेल दुकानों से जब्त किया है। कार्रवाई में करीब 1 लाख 77 हजार 600 रुपए कीमत की 592 जोड़ी नकली चप्पल बरामद की गई हैं। पुलिस ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ धारा 51 और 63 कॉपीराइट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट से लगी दीवार अचानक गिरी

बालाघाट। बालाघाट के रामनगर में एक निर्माणाधीन मकान के बेसमेंट से लगी दीवार अचानक गिर गई। इस हादसे में वहां काम कर रहे तीन मजदूर मलबे के नीचे दब गए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और स्थानीय युवकों ने मिलकर तुरंत राहत का काम शुरू किया और मलबे से तीनों मजदूरों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया।

छिंदवाड़ा में लगातार गिरते जलस्तर के कारण पेयजल संकट

छिंदवाड़ा। शहर में मानसूनी बारिश की कमी और जलस्रोतों के लगातार गिरते जलस्तर के कारण पेयजल संकट की स्थिति बन गई है। इसे देखते हुए पेयजल विभाग ने अब शहर में एक दिन के अंतराल पर पानी सप्लाई करने का फैसला किया है। पानी की यह नई व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है।

एकीकृत माध्यमिक शाला गोपालनगर की घटना: एसडीएम ने दिए जांच के आदेश

मध्याह्न भोजन के दौरान स्कूल भवन की छत का प्लास्टर गिरा, तीन छात्राएं घायल; एक रेफर

एक शिक्षिका के भरोसे चल रहा 8वीं तक का स्कूल

प्रभारी हाजिरी लगाकर लौटे; 15 किमी दूर स्कूल पहुंचने में जनशिक्षक को लगे 3 घंटे

सिरोंज। दोपहर मेट्रो

एकीकृत माध्यमिक शाला गोपालनगर में गत दिवस दोपहर मेंबड़ा हादसा हो गया। मध्याह्न भोजन के दौरान जर्जर स्कूल भवन की छत का प्लास्टर बच्चों पर आ गिरा। हादसे में पहली कक्षा की छात्रा लव्यांशी अहिरवार के सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं दो अन्य छात्राएं रिया और शिवकाशी भी घायल हुई हैं। लव्यांशी का प्राथमिक उपचार सिरोंज में कराने के बाद एसडीएम के निर्देश पर सीटी स्कैन के लिए उसे विदिशा रेफर किया गया है।

गोपालनगर स्कूल में तीन शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन हादसे के वक्त स्कूल में केवल प्राथमिक शिक्षिका अपेक्षा शर्मा ही मौजूद थीं। वही पहली से आठवीं तक की कक्षाओं की व्यवस्था संभाल रही थीं। स्कूल के प्रभारी जनक खेस्स बुधवार सुबह स्कूल आए और हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर करके वापस लौट गए। दूसरे शिक्षक भगवानदास बैरागी बीआरसी कार्यालय से किताबें लेने के लिए सिरोंज में ही रुके हुए थे। बीआरसी जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की जानकारी लगते ही मैं खुद छात्रा से मिलने अस्पताल पहुंचा था। जनशिक्षक को भी जांच के लिए स्कूल भेजा गया है। स्कूल को मरम्मत के लिए हर साल 50 हजार रुपए मिलते हैं। इसके उपयोग और घटना की हम जांच करवा रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाई होगी।

एसडीएम ने रेफर कराया, शाम 5 बजे भेजी एंबुलेंस

एसडीएम हरिशंकर विश्वकर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत बच्ची को सिटी स्कैन के लिए विदिशा भेजने के निर्देश दिए। शाम 5 बजे एंबुलेंस से लव्यांशी को विदिशा भेजा गया। हादसे में घायल अन्य दो छात्राएं रिया और शिवकाशी को भी चोटें आई हैं।

भोजन के दौरान हादसा मलबे में दबी मिली छात्रा

दोपहर करीब 1 बजे मध्याह्न भोजन का समय हुआ तो शिक्षिका अपेक्षा शर्मा ने प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को एक ही कक्ष में बैठा दिया। बच्चे भोजन कर ही रहे थे कि अचानक छत के एक हिस्से का प्लास्टर भरभराकर गिर गया। कक्षा में भगदड़ मच गई। शिक्षिका जब भीतर पहुंची तो पहली कक्षा की छात्रा लव्यांशी अहिरवार मलबे में दबी हुई थी। साथी छात्रा रिया और शिवकाशी मलबा हटा रही थीं। मलबा हटाते ही लव्यांशी के सिर से खून की धार बह निकली। शिक्षिका ने तुरंत परिजनों को सूचना देकर घायल छात्रा को इलाज के लिए सिरोंज रवाना कर दिया।

प्राइवेट अस्पताल में कराया इलाज, शिक्षकों ने दिया खर्च

सूचना मिलते ही डायल-112 भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक परिजन बच्ची को लेकर सिरोंज रवाना हो चुके थे। परिजनों ने लिंक रोड स्थित प्राइवेट अस्पताल में लव्यांशी को भर्ती कराया। जानकारी लगने पर स्कूल के दोनों शिक्षक भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इलाज का खर्च देकर वापस लौट गए। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन बच्ची को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे।

आखिर जिम्मेदार कौन...?

रेत ठेका नहीं होने से शासन को 45 करोड़ के राजस्व का नुकसान

शहडोल। दोपहर मेट्रो

शहडोल जिले में रेत खदानों का समय पर ठेका नहीं होने से शासन को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान होने की चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि यदि लगभग 45 करोड़ रुपये का संभावित राजस्व प्रभावित हुआ है तो इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। जानकारों का कहना है कि रेत खदानों का नियमित आवंटन न होने से न केवल सरकारी खजाने को नुकसान होता है, बल्कि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को भी बढ़ावा मिलने की आशंका रहती है। ऐसे मामलों में जिला प्रशासन, खनिज विभाग और संबंधित एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। पूर्व की ऑडिट रिपोर्टों में भी समय पर खनन पट्टों के आवंटन में देरी से राजस्व प्रभावित होने की बात सामने आ चुकी है। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि शासन इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराए और यह स्पष्ट करे कि रेत खदानों का ठेका समय पर क्यों नहीं हुआ। साथ ही यदि लापरवाही के कारण शासन को आर्थिक नुकसान हुआ है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

समर्थन मूल्य: मूंग खरीदी शुरू, कलेक्टर ने बोरी उठाकर तौल कांटे पर रखी, उपार्जन की शुरुआत

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन का कार्य गत दिवस विधिवत शुरू हो गया। इटारसी स्थित नीलम वेयरहाउस में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने किसानों के साथ तौल कांटों का पूजन कर खरीदी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं मूंग की बोरी उठाकर तौल कांटे पर रखी और उपार्जन की औपचारिक शुरुआत की।

शुभारंभ के बाद कलेक्टर मिश्रा ने उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। कलेक्टर दो किसानों को शॉल भेंट की,उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी हो। पंजीयन, तौल, परिवहन और भुगतान सहित किसी भी स्तर पर किसानों को परेशानी न हो तथा शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि जिले के सभी मूंग उपार्जन केंद्र चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जा रहे हैं। कुछ केंद्रों पर खरीदी शुरू हो चुकी है और गुरुवार शाम तक सभी केंद्र पूर्ण क्षमता के साथ संचालित होने लगेंगे। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु को देखते हुए भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिन गोदामों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, वहीं खरीदी की जा रही है। मूंग की बोरियों को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल, शेड और अन्य आवश्यक इंतजाम किए गए हैं, ताकि उपज की गुणवत्ता बनी रहे। निरीक्षण के दौरान तौल व्यवस्था, गुणवत्ता परीक्षण और भंडारण व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया। किसानों ने प्रशासन की तैयारियों पर संतोष जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि इस वर्ष खरीदी प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के संपन्न होगी। इस अवसर पर एसडीएम नीलेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर नीता कोरी, तहसीलदार सुनीता साहनी, वेयरहाउसिंग डीएम वासुदेव दवांडे, उपसंचालक कृषि रविकांत सिंह, डीआरसीएस शिवम मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।

ऊहर में संस्कारों की नई पाठशाला का शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर ने खोले शिक्षा के द्वार

गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो

शिक्षा, संस्कार और भारतीय संस्कृति के समन्वय का नया अध्याय समीपस्थ ग्राम ऊहर में प्रारंभ हुआ। बेतवा ग्राम भारती शिक्षा समिति द्वारा संचालित नवीन सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय का शुभारंभ वैदिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में नवप्रवेशी विद्यार्थियों का पारंपरिक विद्यारंभ संस्कार कराया गया, जिसने पूरे कार्यक्रम को आध्यात्मिक और संस्कारमय स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं वंदना के साथ हुआ। समारोह की अध्यक्षता श्री रामजानकी आश्रम ऊहर के महंत ऋषिदास जी महाराज ने की। उन्होंने कहा कि विद्या भारती के विद्यालय केवल शिक्षा के केंद्र नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, चरित्र निर्माण, अनुशासन और भारतीय जीवन मूल्यों के संवाहक हैं। उन्होंने नवप्रवेशी विद्यार्थियों को तिलक लगाकर विद्यारंभ संस्कार कराया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्य अतिथि राजेश तिवारी ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शिक्षा ही बच्चों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और जड़ों से जोड़ने का कार्य करती है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को संस्कारयुक्त शिक्षा से जोड़ने का आग्रह किया।

विशिष्ट अतिथि राजेश माथुर ने समाज निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कारित शिक्षा से ही सशक्त और जिम्मेदार नागरिक तैयार होते हैं। शिक्षा समिति के सचिव विजय भावसार ने विद्यालय की कार्यप्रणाली और विद्या भारती के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि विद्यालय का लक्ष्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना, अनुशासन, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास करना है।

महिला से दुष्कर्म, आरोपी दे रहा फोटो वायरल करने की धमकी

शादी की बात आई तो ब्लैकमेलिंग पर उतरा

धार। दोपहर मेट्रो

शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत एक निजी बैंक में साथ काम करने वाले सहकर्मी ने शादी का झांसा देकर एक विवाहित महिला के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म किया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने न सिर्फ उसे शादी का झूठा भरोसा दिया, बल्कि बाद में उनके निजी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता की दूसरी जगह तय हो रही शादी को भी तुड़वा दिया। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता और आरोपी सुमित शर्मा पिता सुभाष शर्मा निवासी पट्टा चौपाटी दोनों शहर के एक ही निजी बैंक में काम करते थे। पिछले तीन सालों से दोनों एक-दूसरे को जानते थे। काम के दौरान दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और उन्होंने अपने-अपने शादीशुदा जीवन के तनाव को एक-दूसरे से साझा किया। आरोपी सुमित ने महिला को बताया कि उसकी पत्नी का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है। वहीं, पीड़िता ने भी साझा किया कि उसका पति भी उसे ठीक से नहीं रखता है। समान पारिवारिक परिस्थितियों और हमदर्दी के चलते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं।

आरोपी सुमित ने महिला को भरोसा दिलाया कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर उससे शादी कर लेगा। इस झांसे में लेकर वह महिला को सुंदरवन कॉलोनी स्थित एक स्थान पर ले गया, जहां उसने पहली बार महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस वादे और भरोसे के बीच महिला का अपने पति से कानूनी रूप से तलाक भी हो गया। तलाक होने के बाद जब पीड़िता ने सुमित पर शादी करने का दबाव बनाया, तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया।

यूपी में तय हो रहा रिश्ता भी तुड़वाया

परेशान होकर जब महिला के परिजनों ने उसके लिए उत्तर प्रदेश में एक नया रिश्ता देखा और शादी की बात आगे बढ़ाई, तो आरोपी ने पीड़िता के होने वाले ससुराल वालों को दोनों के निजी फोटो भेज दिए, जिसके कारण वह रिश्ता टूट गया। आरोपी पीड़िता को कहीं भी और शादी नहीं करने दे रहा था और लगातार ब्लैकमेल कर रहा था।

थाने पहुंची पीड़िता

आरोपी की प्रताड़ना और धमकी से तंग आकर पीड़िता अपने परिजनों के साथ कोतवाली थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई । पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर सुमित पिता सुभाष शर्मा निवासी पट्टा चौपाटी पर दुष्कर्म की सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तकनीकी एवं मुखबिर तंत्र की सहायता से आरोपी सुमित को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

मेट्रो एंकर राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रभक्ति के संकल्प के साथ विद्यार्थियों व स्टाफ ने किया सामूहिक गायन

वंदे मातरम् के गायन से गुंजायमान हुआ कृषि महाविद्यालय परिसर

गंजबासौदा। दोपहर मेट्रो

जिला कलेक्टर विदिशा के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस पर आयोजित होने वाले वंदे मातरम् कार्यक्रम के तहत गत दिवस कृषि महाविद्यालय में गरिमामय आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिष्ठाता प्रभारी डॉ. जी.आर. बंसल के निर्देशन में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रभक्ति के पवित्र गीत वंदे मातरम् के सामूहिक गायन से हुई। महाविद्यालय के समस्त तकनीकी अधिकारियों, शैक्षणिक स्टाफ एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए राष्ट्र के प्रति अपनी आस्था और समर्पण का परिचय दिया। इस अवसर पर अधिष्ठाता प्रभारी डॉ. जी.आर. बंसल ने कहा कि शासन की मंशा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रभक्ति तथा कर्तव्यनिष्ठा की भावना को सुदृढ़ करना है। ऐसे आयोजन युवाओं में देश के प्रति सम्मान, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाविद्यालय परिवार ने राष्ट्रहित एवं राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजनों को निरंतर आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

कार्रवाई: पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी को भी बनाया आरोपी, सामान और बाइक जब्त

प्लेट्स और तांबा चुराने वाली शातिर गैंग पकड़ाई, कबाड़ी सहित 4 गिरफ्तार

धार। दोपहर मेट्रो

निसरपुर और कुक्षी थाना पुलिस की संयुक्त ने मेघनाथ घाट पर निर्माणाधीन क्रूज टर्मिनल से लोहे की एमएस प्लेट्स और नर्मदा किनारे से किसानों के वाटर पंप काटकर तांबे के तार चुराने वाले 3 शातिर चोरों सहित चोरी का माल खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लाखों का मशरूका और वारदात में इस्तेमाल की गई दो बाइक बरामद की गई हैं।

पिछले कुछ समय से नर्मदा नदी के किनारे खारवा नाला करोंदिया, आमला बावड़ी, पुराना कोठडा के किसानों के खेतों और कुओं से लगातार पानी की मोटर पंप काटकर तांबे के तार चोरी होने की वारदातें सामने आ रही थीं। जून महीने में ही इस संबंध में अलग-अलग फरियादियों की रिपोर्ट पर कुक्षी थाने में 4 से 5 मामले दर्ज किए गए थे। किसानों के मोटर पंप चोरी होने से क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश था। मामले की गंभीरता को देखते हुए धार पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने थाना प्रभारी कुक्षी निरीक्षक राजेश यादव एवं चौकी प्रभारी निसरपुर उनि रवि वास्के को त्वरित कार्रवाई और पतारसी के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं एसडीओपी कुक्षी सुनील गुप्ता के मार्गदर्शन में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थलों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सायबर सेल धार से पीएसटीएन डाटा निकालकर संदेही मोबाइल नंबरों को ट्रैक किया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चंदनखेड़ी के तीन युवकों पंकज अनारे, शैलेन्द्र रामसिंह और आयुष बघेल को हिरासत में लिया। शुरुआत में आनाकानी करने के बाद, जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने चोरी की वारदातें कबूली।

कबाड़ी की दुकान पर बेचते थे माल

पूछताछ में आरोपियों ने कुक्षी के मेघनाथ घाट पर पर्यटकों के लिए बन रहे क्रूज टर्मिनल से लोहे की 176 एमएस प्लेट्स चोरी करना कबूल किया। इसके अलावा, उन्होंने नर्मदा किनारे अलग-अलग स्थानों से किसानों की करीब 25 मोटर पंप काटकर उनके अंदर का तांबा चोरी करना भी स्वीकार किया। आरोपी यह सारा माल ग्राम कोणदा के कबाड़ी जगदीश पिता भूरिया अलोने की भंगार दुकान पर बेचते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कबाड़ी को भी सह-आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से क्रूज टर्मिनल से चोरी हुई 176 प्लेट्स कीमती 88,000, किसानों की मोटरों से निकाला गया 97 किलो तांबा जिसकी कीमत 1,74,600 है और वारदात में उपयोग की गई दो बाइक भी जब्त की है। कार्रवाई में कुक्षी थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश यादव, निसरपुर चौकी प्रभारी उनि रवि वास्के, सउनि भुवान चौहान, प्र.आर. प्रकाश, आरक्षक सुभाष चौहान, रवि, गौरव, अर्जुन, किशन, थानसिंह के साथ-साथ सायबर सेल प्रभारी उनि प्रशांत गुंजाल, आरक्षक प्रशांत और शुभम की मुख्य व सराहनीय भूमिका रही।

न्यूज विंडो

शासकीय महाविद्यालय में हुआ दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन

तेंदूखेड़ा। तेंदूखेड़ा नगर के अमर वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय में मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार एक जुलाई को तीन दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में नव प्रवेशित विद्यार्थिओं का स्वागत तिलक लगा कर किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य यशवंत अहिरवार द्वारा विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय की स्थापना, उपलब्धियों शैक्षणिक सुविधाओं, एवं अन्य संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में प्रवेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रभारी डॉ अरुणेन्द्र कुमार पटेल द्वारा विद्यार्थिओं को प्रवेश प्रक्रिया, स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना संबंधी अध्यादेश एवं विषय चयन से अवगत कराते हुए पाठ्यक्रम संरचना एमओओसीएस कोर्सेस, परीक्षा संरचना की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में डॉ संध्या स्थापक द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कल्याण (एनटीएफ) विषय पर उद्बोधन दिया गया, साथ ही उनके द्वारा एंटी रैगिंग, महिला सुरक्षा, छात्र आचरण, विद्यार्थियों के संस्था के प्रति दायित्व विषय पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉ मनीषा कुमारिया ने किया। कार्यक्रम में समस्त शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के समापन में डॉ नन्दकिशोर निकोसे द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

स्कूल बसों की बदहाल स्थिति पर उठ रहे सवाल, हो सकता है हादसा

शहडोल। शहडोल संभाग के अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। क्षेत्र में संचालित कई निजी एवं शासकीय विद्यालयों की बसों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार कुछ विद्यालयों में 20 से 25 वर्ष पुरानी बसों का संचालन किया जा रहा है। आरोप है कि कई वाहनों की बॉडी जर्जर हो चुकी है, सीटें स्थानीय स्तर पर ठेकेदारों द्वारा लगाई गई हैं तथा कुछ बसों की छत तक क्षतिग्रस्त बताई जा रही है। वहीं कई वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की वैधता को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। विशेष रूप से संदीपनी विद्यालय सहित कुछ अन्य स्कूलों में संचालित वाहनों की स्थिति को लेकर अभिभावकों में चिंता बढ़ रही है। लोगों का कहना है कि कई बसें ऐसी दिखाई देती हैं मानो उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया जाना चाहिए, फिर भी उन्हीं वाहनों में प्रतिदिन बच्चों को ढोया जा रहा है। क्षेत्र के नागरिकों का सवाल है कि आखिर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और यातायात विभाग को ये वाहन क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं यदि वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र और परमिट मानकों के अनुरूप नहीं हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने अनूपपुर, शहडोल और उमरिया के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, संभागीय आयुक्त तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से तत्काल जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और स्कूल वाहनों का व्यापक निरीक्षण कराया जाना चाहिए। लोगों का यह भी कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही जागेगा। बच्चों की जान जोखिम में डालने वाली किसी भी लापरवाही पर समय रहते कार्रवाई होना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

तेंदूखेड़ा जनपद सीईओ मनीष बागरी का निधन

तेंदूखेड़ा। जनपद पंचायत तेंदूखेड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ मनीष बागरी 42 वर्ष का बीती रात्रि आकस्मिक निधन हो गया। ऐसा चिकित्सकों द्वारा बताया गया है। हालांकि जब भी सुबह 10 बजे तक वे सोकर नहीं उठे तो उन्हें कर्मचारियों ने उठाया लेकिन किसी तरह की हलचल न होने के कारण अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया, उनके निधन की खबर मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं नगरवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात्रि में बागरी अपने जनपद पंचायत परिसर स्थित शासकीय आवास पर भोजन करने के बाद विश्राम के लिए चले गए थे। बुधवार सुबह लगभग 10 बजे जब कर्मचारी उन्हें चाय देने पहुंचे तो काफी आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कर्मचारियों ने तत्काल उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदूखेड़ा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके आकस्मिक निधन की जानकारी लगने पर मध्य प्रदेश शासन की मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जिले के अधिकारी सहित सब डिवीजन के अधिकारी पहुंचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम सी.जी. गोस्वामी, तहसीलदार विवेक व्यास, एसडीओ (वन) प्रतीक दुबे, वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रेयांश जैन, तारादेही वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेंद्र गुर्जर, प्रभारी कलेक्टर दमोह प्रवीण फुलपगार, एसडीएम दमोह सौरभ गंधर्व, एसडीओपी अर्चना अहीर, नगर निरीक्षक रवींद्र बागरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनपद पंचायतों के कई मुख्य कार्यपालन अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और शोक व्यक्त किया।

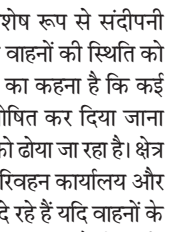

नीमच में कांग्रेस का राजनीतिक माहौल गरमाया

नगरपालिका परिषद की बैठक के बाद आपस में भिड़े कांग्रेस नेता

नीमच। दोपहर मेट्रो

नगरपालिका परिषद के विशेष सम्मेलन में करीब 350 नामांतरण प्रकरणों को मंजूरी मिलने के बीच एक नामांतरण प्रस्ताव ऐसा रहा, जिसने बैठक समाप्त होने के बाद कांग्रेस का राजनीतिक माहौल गरमा दिया। इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस पार्षदों के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया। परिषद कक्ष के बाहर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति और वार्ड क्रमांक-37 की पार्षद के प्रतिनिधि शराफत अली के बीच तीखी बहस, धक्का-मुक्की और नोक-झोंक हो गई। मौके पर मौजूद अन्य पार्षदों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

पुरानी नगर पालिका भवन (बंगला नंबर-60) में बीते दिन विशेष सम्मेलन में कुल 44 प्रस्ताव बहुमत से पारित किए गए। इनमें लगभग 350 नामांतरण प्रकरण भी शामिल थे। विवाद की जड़ बोहरा समाज की महिला सकीना के नामांतरण प्रस्ताव को माना जा रहा है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने पहले आपत्ति दर्ज कराई थी। परिषद के भीतर शुरू हुई बहस बैठक समाप्त होने के बाद बाहर खुलकर सामने आ गई। विवाद के बाद शराफत अली ने कहा कि संबंधित नामांतरण सभी नियमों और तथ्यों के परीक्षण के बाद परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया। उनका कहना था कि जब सैकड़ों नामांतरण एक साथ पारित किए गए, तब केवल एक प्रकरण पर आपत्ति उठाना समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष प्रजापति ने यह कहा कि पैसे लेकर नामांतरण पास कराया गया। शराफत अली ने इसे निराधार बताते हुए कहा कि बिना किसी प्रमाण के ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधित महिला लंबे समय से परेशान थी और उसका नामांतरण पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया के तहत स्वीकृत हुआ है। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने पूरे घटनाक्रम को गलतफहमी बताया। उन्होंने कहा कि उनका आरोप कांग्रेस के किसी पार्षद पर नहीं, बल्कि भाजपा पार्षदों और नगर पालिका में कथित रूप से सक्रिय उस व्यवस्था पर था। जहां पैसे लेकर आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के उपयोग में बदलाव जैसे मामलों को मंजूरी दिलाने के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथियों पर उन्होंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की और बाहर हुआ विवाद केवल उनके बयान को गलत ढंग से समझने के कारण हुआ।

सरकारी इमामबाड़ा हुआ सील, ताजिया कमेटी ने सौंपा कब्जा

धार। दोपहर मेट्रो

इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बुधवार दोपहर 12 बजे प्रशासन ने शहर के हटवाड़ा स्थित सरकारी इमामबाड़े को दोबारा सील कर दिया है। पूरी कार्रवाई पीडब्ल्यूडी के एसडीओ भास्कर मालवीय और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बेहद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान ताजिया कमेटी के पदाधिकारियों ने इमामबाड़े की चाबी आधिकारिक तौर पर प्रशासन को सौंप दी।

दरअसल इमामबाड़े को लेकर लंबे समय से न्यायालय में मामला विचाराधीन है। हाल ही में मोहर्रम के मद्देनजर धार्मिक कार्यक्रमों को संपन्न कराने के लिए कोर्ट ने इसे एक निश्चित अवधि के लिए ताजिया कमेटी को सौंपने का आदेश दिया था। न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा पूरी होते ही प्रशासन ने कानूनन इसे दोबारा अपने नियंत्रण में ले लिया है। मामले की संवेदनशीलता और सुरक्षा को भांपते हुए प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। सुरक्षा व्यवस्था की मुख्य बातें इस प्रकार रहीं। इमामबाड़ा परिसर और उसके आसपास के संवेदनशील इलाकों में लगभग 150 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखने के लिए इमामबाड़े के ठीक बाहर एक मिनी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कानून-व्यवस्था में कोई खलल न पड़े, इसके लिए पूरे क्षेत्र की निगरानी आधुनिक ड्रोन कैमरों से की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने मीडिया को बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से माननीय न्यायालय के निर्देशों के तहत की गई है।

डीवीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में धूमधाम से मनाया गया डॉक्टर्स डे

कोतमा। दोपहर मेट्रो

डीवीएम हायर सेकेंडरी स्कूल, कोतमा में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर गरिमामय एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान के चिकित्सा अधिकारी डॉ. विपिन कुमार रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य भगवान दास मिश्रा तथा विद्यालय के डायरेक्टर बी.एन. ओझा उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके बाद विद्यालय के नन्हे-मुन्ने विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के महत्व पर अपने विचार भी व्यक्त किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगवान दास मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सर्वोच्च माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए डॉ. विपिन कुमार गरीब, आदिवासी एवं वंचित वर्ग के लोगों के लिए समर्पित भाव से निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनकी सेवाओं और मानवीय दृष्टिकोण ने आमजन के बीच चिकित्सकों के सम्मान को और अधिक बढ़ाया है। समाज उनके सकारात्मक कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित भी कर रहा है।

विद्यालय के डायरेक्टर बी.एन. ओझा ने अपने संबोधन में कहा कि चिकित्सक समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनका समर्पण, सेवा और त्याग नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा चिकित्सकों का सम्मान करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि डॉ. विपिन कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, संतुलित आहार लेने, नियमित व्यायाम करने और स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने अपने प्रेरक उद्बोधन के माध्यम से बच्चों को जीवन में अनुशासन, परिश्रम और सेवा भाव अपनाने के लिए प्रेरित किया तथा बताया कि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों का शाल श्रीफल पुष्पगुच्छ एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं, विद्यार्थी उपस्थित रहे।

उमरिया जिले की तहसीलों में भ्रष्टाचार के आरोप, हर काम का रेट फिक्स होने का दावा

उमरिया।। दोपहर मेट्रो

प्रदेश सरकार सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का दावा करती है, लेकिन उमरिया जिले की मानपुर, बांधवगढ़, पाली और चंदिया तहसीलों को लेकर ग्रामीणों एवं आवेदकों द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि राजस्व विभाग के अधिकांश कार्य बिना कथित लेन-देन के समय पर नहीं हो रहे हैं। उनका आरोप है कि खसरा-नकल, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, जमीन विक्रय अनुमति, रजिस्ट्री के बाद नामांतरण और न्यायालयीन आदेशों की प्रतिलिपि जैसे कार्यों के लिए अलग-अलग रकम मांगी जाती है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि रजिस्ट्री होने के बाद भी नामांतरण के लिए हजारों

सीमांकन में भी रिश्वत

ग्रामीणों का कहना है कि सीमांकन की सरकारी फीस अलग होने के बावजूद कई मामलों में अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है। राशि नहीं देने पर बार-बार तारीख देने और फाइल लंबित रखने के आरोप लगाए हैं।

प्रति के लिए कथित मांग

कुछ शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि राजस्व न्यायालय से आदेश मिलने के बाद भी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने में देरी की जाती है तथा इसके लिए भी अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही हैं।

रुपये की मांग की जाती है। पैसे नहीं देने पर फाइल महीनों तक लंबित रखी जाती है, जिससे किसानों और आम नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है।

नकली शराब बिकने की चर्चा

अनूपपुर। जिले की कुछ शराब दुकानों पर कथित रूप से डुप्लीकेट शराब बेचे जाने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। नकली या मिलावटी शराब की बिक्री की शिकायतें मिल रही हैं, तो आबकारी विभाग और पुलिस को संयुक्त जांच कर सच्चाई सामने लानी चाहिए। नकली शराब की पहचान केवल प्रयोगशाला जांच से ही संभव होती है। समय-समय पर नकली शराब के खिलाफ कार्रवाई होती रही है।

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अब्दुलमाजीद अब्दुलहादी अब्बासी (ADDULMAJID ABDULHADI ABBASI) था जो कि अब बदल कर अब्दुल माजिद अब्बासी (ABDUL MAJID ABBASI) हो गया अतः अब भविष्य में मुझे अब्दुल माजिद अब्बासी (ABDUL MAJID ABBASI) के नाम से जाना एवं पहचाना जाए पुत्र : अब्दुल हादी अब्बासी पता : म. न.114/24 आबादी एरिया खानुगांव हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश 462001

मोबाइल न. 7470466021

मेट्रो एंकर केसुर और सादलपुर में पुलिस का साइबर सुरक्षा अभियान 2.0....

सेफ क्लिक के जरिए किया जागरूक

धार। दोपहर मेट्रो

प्रदेश में बढ़ते सायबर अपराधों पर लगाम लगाने और आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा पूरे प्रदेश में सायबर सुरक्षा अभियान 2.0 सेफ क्लिक चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में धार पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारुल बेलापुरकर एवं अनुविभागीय अधिकारी अरविन्द सिंह तोमर के मार्गदर्शन में धार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के तहत केसुर बस स्टैंड पर नागरिकों को सायबर अपराधों के प्रति सचेत किया गया, वहीं सादलपुर थाना क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाया गया।

थाना प्रभारी सादलपुर निरीक्षक सविता चौधरी के निर्देशन में उपनिरीक्षक राकेश मौर्य, प्रधान आरक्षक किशोरसिंह चौहान और महिला आरक्षक शीतल चौहान की टीम ने शासकीय हाई स्कूल, ग्राम सादलपुर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।कार्यक्रम में स्कूल की प्राचार्या अनिता, अन्य शिक्षकगण और लगभग 60 छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। पुलिस टीम ने उपस्थित सभी लोगों को सायबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में विस्तार से समझाया। पुलिस ने ने बताया कि किसी भी अज्ञात नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को उठाने से बचें, यह ब्लैकमेलिंग का जरिया हो सकता है। सोशल मीडिया या मैसेज पर आने वाले किसी भी अज्ञात लिंक या फोटो पर बिना जांचे क्लिक न करें।

कार्यालय थाना प्रभारी थाना अवधपुरी नगरीय पुलिस भोपाल

क्रमांक / थाना अवध/गुमईसान / 181 /26 दिनांक 27/6/26

सूचना का प्रकाशन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि थाना अवधपुरी भोपाल के गुमईसान क्र. 24/25 गुमशुदा भास्कर बाबू यादव उर्भ भास्कर यादव पिता जगदीशचन्द यादव आयु 35 साल निवासी मकान न.1/15 प्यूस नगर अवधपुरी भोपाल दिनांक 13/7/25 को घर से बिना बताये कही चले जाने व घर वापस नहीं आने पर परिजनों द्वारा अपने परिवार व रिस्तेदारों में तलास किया कोई पता नहीं चलने पर थाना अवधपुरी भोपाल में गुमईसान क्र. 24/25 दिनांक 17/7/25 को पंजीबद्ध कराया गया जिसकी जांच चल रही है। गुमशुदा का हुलिया रंग गोरा चेहरा अण्डाकर, कद 5.10 फीट, बाल काले, आंख काली, मूछे, पैन्ट शर्ट पहने है। गुमशुदा के संबंध में कोई जानकारी मिले तो थाना अवधपुरी भोपाल को मो. न.9479990584, मो.न. 7049104570 पर सूचित करे।

जी-15079/26

थाना प्रभारी थाना अवधपुरी
जिला-भोपाल

टी-20 सीरीज: कप्तान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा की शानदार पारियों पर फिरा पानी

बारिश की भेंट चढ़ गया भारत और इंग्लैंड का पहला टी20 मैच

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन का मजबूत लक्ष्य रखा था, लेकिन इंग्लैंड अपनी पारी शुरू भी नहीं कर सका। लगातार बारिश और गीले मैदान की वजह से आखिरकार अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला लिया। ऐसे में श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा की शानदार पारियां भी टीम के किसी काम नहीं आ सकीं।

हालांकि, बारिश रुकने का इंतजार काफी देर तक किया गया। मैच शुरू कराने के लिए कट-ऑफ समय में करीब 45 मिनट बाकी थे, लेकिन मैदान खेलने लायक नहीं बन पाया। ग्राउंड स्टाफ ने पूरे मैदान को कवर से ढक रखा था। कुछ समय बाद बारिश की रफ्तार जरूर कम हुई, लेकिन बूंदाबांदी जारी रही। ऐसे में मैदान तैयार करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा और मुकाबला बिना किसी नतीजे के खत्म घोषित कर दिया गया। अगर खेल शुरू हो जाता तो 190 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता था।

चेस्टर-ले-स्ट्रीट का यह मैदान भारत के लिए एक बार फिर अधूरी कहानी लेकर आया। इससे पहले 2002 और 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ यहां खेले गए वनडे मुकाबले भी बारिश के कारण बिना नतीजे के खत्म हुए थे। अब 2026 का पहला टी20 भी उसी सूची में जुड़ गया है। दोनों टीमें अब मैनचेस्टर के लिए रवाना होंगी, जहां शनिवार को सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा।

ऐसी रही भारत की बैटिंग

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए सात विकेट पर 189 रन बनाए। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। उसने दूसरे ही ओवर में संजू सैमसन और ईशान किशन के विकेट गंवा दिए। संजू सैमसन (1 रन) को साकिब महमूद ने टॉम बैंटन के हाथों कैच आउट कराया। वहीं ईशान किशन खाता खोले बगैर रन आउट हुए। यहां से अभिषेक शर्मा और कप्तान श्रेयस अय्यर के बीच तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी हुई। अभिषेक शर्मा ने 6 चौके और चार छक्के की मदद से सिर्फ 24 गेंदों पर 59 रन बनाए। अभिषेक ने अपना अर्धशतक सिर्फ 20 गेंदों पर ही कम्पलीट कर लिया। सैम करन ने एक धीमी गेंद पर अभिषेक को आउट किया। तिलक वर्मा (13 रन) कुछ खास नहीं कर सके और साकिब महमूद का शिकार बने। फिर श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 41 रन जोड़े। साकिब महमूद ने श्रेयस अय्यर को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। श्रेयस अय्यर ने 6 चौके और एक छक्के की मदद से 47 गेंदों पर 68 रन बनाए। श्रेयस ने अपनी फिफ्टी 38 गेंदों पर पूरी की, जो टी20 इंटरनेशनल में उनकी सबसे धीमी फिफ्टी रही। श्रेयस के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे हर्षित राणा खाता भी नहीं खोल पाए और उन्हें आदिल राशिद ने चलता किया। यहां से शिवम दुबे ने कुछ बड़े शॉट्स खेलकर भारत को अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। शिवम दुबे ने 21 बॉल पर नाबाद 42 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और तीन छक्के शामिल रहे। अक्षर पटेल (3 रन) पारी की आखिरी बॉल पर रन आउट हुए। इंग्लैंड की ओर से साकिब महमूद ने सबसे ज्यादा तीन विकेट झटके।

फीफा विश्व कप 2026, 90 मिनट तक 2-2 की बराबरी पर रहा मुकाबला

बेल्जियम की दमदार वापसी, सेनेगल को 3-2 से हराकर अगले दौर में पहुंचा

सिएटल, एजेंसी

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में बेल्जियम ने बेहद रोमांचक मुकाबले में सेनेगल को 3-2 से हराकर अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। निर्धारित 90 मिनट तक मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। सेनेगल के लिए इस्माइला सार ने 51वें मिनट और हबीब डियारा ने 24वें मिनट में गोल दागे, जबकि बेल्जियम की ओर से रोमेलू लुकाकू ने 86वें मिनट में बराबरी दिलाई और यूरी टाईलेमांस ने 89वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। हालांकि मुकाबला अतिरिक्त समय तक पहुंचा, जहां 120+5वें मिनट में यूरी टाईलेमांस ने पेनल्टी पर गोल करते हुए बेल्जियम को 3-2 की यादगार जीत दिला दी। इस जीत के साथ बेल्जियम ने टूर्नामेंट के राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया।

फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में बेल्जियम और सेनेगल के बीच खेला गया मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा। मैच की शुरुआत में सेनेगल ने शानदार खेल दिखाया और 24वें मिनट में हबीब डियारा के गोल की बदौलत 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में 51वें मिनट पर इस्माइला सार ने गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। लगातार दो गोल खाने के बाद बेल्जियम पर टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा था।

आखिरी मिनटों में बेल्जियम ने दिखाया दम

दो गोल से पिछड़ने के बावजूद बेल्जियम ने हार नहीं मानी और मैच के अंतिम मिनटों में शानदार वापसी की। 86वें मिनट में स्टार स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू ने गोल कर टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। इसके बाद 89वें मिनट में यूरी टाईलेमांस ने शानदार फिनिश करते हुए स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं और मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंच गया। अतिरिक्त समय में दोनों टीमों ने कई आक्रामक प्रयास किए, लेकिन कोई भी टीम बढ़त नहीं बना सकी। मुकाबला जब पेनल्टी शूटआउट की ओर बढ़ता नजर आ रहा था, तभी अतिरिक्त समय के 120+5वें मिनट में बेल्जियम को पेनल्टी मिल गई। यूरी टाईलेमांस ने दबाव में भी बेहतरीन शॉट लगाते हुए गेंद को गोलपोस्ट में पहुंचा दिया और बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिला दी।

बेल्जियम ने राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह

इस जीत के साथ बेल्जियम ने फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं, दो गोल की बढ़त हासिल करने के बावजूद सेनेगल को हार का सामना करना पड़ा और उसका विश्व कप अभियान राउंड ऑफ 32 में ही समाप्त हो गया। बेल्जियम की जीत के सबसे बड़े नायक यूरी टाईलेमांस रहे, जिन्होंने दो गोल कर टीम को अगले दौर में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं, रोमेलू लुकाकू का गोल भी टीम की वापसी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

फीफा का खुलासा-मौजूदा विश्व कप के ग्रुप स्टेज में 89 हजार अभद्र पोस्ट चिन्हित

न्यूयॉर्क। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज के दौरान खिलाड़ियों, टीमों और मैच अधिकारियों को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर किए गए अभद्र और आपत्तिजनक पोस्ट में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। फीफा ने बुधवार को बताया कि उसकी डिजिटल मॉनिटरिंग टीम ने ग्रुप स्टेज के दौरान 89,000 आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट की पहचान की। यह 2022 कतर विश्व कप की तुलना में 13 गुना अधिक हैं। फीफा के सोशल मीडिया प्रोटेक्शन सर्विस (एसएमपीएस) ने इस दौरान 60 लाख से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट और कमेंट्स का विश्लेषण किया। यह संख्या 2022 विश्व कप की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक रही। इनमें से 11 प्रतिशत पोस्ट नस्लीय दुर्व्यवहार से संबंधित थीं। फीफा के अनुसार, ग्रुप स्टेज के दौरान नस्लीय टिप्पणी और भेदभावपूर्ण पोस्ट का अनुपात 2022 विश्व कप की तुलना में तीन प्रतिशत बढ़ा है। संगठन ने इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सबसे गंभीर और आपत्तिजनक सामग्री में बढ़ोतरी बताया है। फीफा ने कहा कि सोशल मीडिया प्रोटेक्शन सर्विस (एसएमपीएस) सभी भाग लेने वाली टीमों, खिलाड़ियों, कोचों और मैच अधिकारियों को सोशल मीडिया पर होने वाले नस्लीय, भेदभावपूर्ण और धमकी भरे संदेशों से बचाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। यह प्रणाली अत्याधुनिक तकनीक और मानव मॉडरेशन के जरिए आपत्तिजनक सामग्री की पहचान कर उसे फ़िल्टर और ब्लॉक करती है।

ईशान किशन का बड़ा धमाका

आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 के सिंहासन पर किया कब्जा अभिषेक शर्मा से छिना ताज

दुबई, एजेंसी

भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने आईसीसी की ताजा टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की रैंकिंग में इतिहास रच दिया है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पहली बार दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज का ताज अपने नाम किया है। उन्होंने अपने ही साथी अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजीशन हासिल किया। अभिषेक शर्मा करीब एक साल तक टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 बने रहे थे, लेकिन अब यह मुकाम ईशान किशन के नाम हो गया है। दोनों भारतीय बल्लेबाजों के बीच फिलहाल सिर्फ 7 रेटिंग पॉइंट का अंतर है, जिससे टॉप पर भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा साफ दिखाई देता है। ईशान किशन को यह उपलब्धि आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में खेली गई दो मैचों की टी20 सीरीज और उससे पहले टी20 विश्व कप में लगातार शानदार प्रदर्शन का इनाम मिली है। टी20 वर्ल्ड कप में ईशान ने 317 रन बनाए थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 का रहा। पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में खेली गई मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। इसी शानदार फॉर्म के दम पर उन्होंने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल करते हुए नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमाया। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहली बार दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक दूसरे और जो रूट तीसरे स्थान पर खिसक गए। वहीं गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह ने फिर से नंबर-1 स्थान हासिल कर लिया है।

विराट और सूर्या के खास क्लब में शामिल

ईशान किशन अब भारत के उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाजों की आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 स्थान हासिल किया है। इस सूची में अब विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन शामिल हैं। ईशान ऐसा करने वाले भारत के चौथे पुरुष बल्लेबाज बन गए हैं।

आयरलैंड के खिलाड़ियों को भी फायदा

आयरलैंड के बल्लेबाज लोर्कन टकर चार स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं रॉस अडेयर छह स्थान ऊपर चढ़कर 84वें नंबर पर पहुंच गए। गेंदबाजों की टी20 रैंकिंग में आयरलैंड के तेज गेंदबाज मैथ्यू हम्फ्रीज एक स्थान ऊपर चढ़कर 25वें नंबर पर पहुंच गए। उन्होंने भारत के खिलाफ दो मैचों में चार विकेट लेकर करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की।

मनोरंजन **बॉलीवुड का कोना**

रोचक अंदाज़ में काज़ोल ने फ़ैंस को हंसाया, बोलीं-

जो मेरे पोस्ट लाइक करते हैं, वही हैं सबसे ज्यादा खुश और स्मार्ट

बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल एक बार फिर अपने मजाकिया अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं। अपनी दमदार अदाकारी के साथ-साथ हाजिरजवाबी के लिए मशहूर काजोल ने सोशल मीडिया पर एक मुस्कुराती हुई सेल्फी साझा की, लेकिन इस बार उनकी तस्वीर से ज्यादा उसके साथ लिखा गया मजेदार कैप्शन लोगों का ध्यान खींच रहा है। पोस्ट सामने आते ही फैंस ने कमेंट्स और लाइक्स की बारिश कर दी।

काजोल ने इंस्टाग्राम पर कार के अंदर क्लिक की गई अपनी एक खूबसूरत सेल्फी शेयर की। तस्वीर में वह गुलाबी रंग की साड़ी में बेहद आकर्षक नजर आ रही हैं। उन्होंने डायमंड और रूबी का चोकर नेकलेस पहना हुआ है, जबकि हल्के मेकअप और मुस्कुराते चेहरे ने उनके लुक को और भी खास बना दिया।

तस्वीर के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा, ष्मेरी बनाई हुई एक स्टडी के अनुसार, जो लोग मेरे पोस्ट लाइक करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में ज्यादा खुश, ज्यादा इंटेलिजेंट और बेहतर दिखने वाले होते हैं, जो उन्हें लाइक नहीं करते।ष् उनका यह कैप्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं। काजोल की इस पोस्ट पर उनके प्रशंसकों ने जमकर प्रतिक्रिया दी। किसी ने उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की तो किसी ने उनकी मुस्कान और सादगी की। कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब पोस्ट को लाइक करना तो बनता है। काजोल अक्सर अपने हल्के-फुल्के और दिलचस्प पोस्ट के जरिए फैंस का मनोरंजन करती रहती हैं।

शाहरुख संग जोड़ी रही सुपरहिट

काजोल ने वर्ष 1992 में बेखुदी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करण अर्जुन, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम..., फना, माय नेम इज खान और तान्हाजीरू द अनसंग वॉरियर जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। काजोल की जोड़ी खास तौर पर शाहरुख खान के साथ दर्शकों की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाती है। वह अभिनेत्री तनुजा और दिवंगत निर्माता शोमू मुखर्जी की बेटी हैं। वर्ष 1999 में उन्होंने अभिनेता अजय देवगन से विवाह किया।

समय के साथ बदल रही हैं टीवी की कहानियां, ईशा बोलीं-

अब मनोरंजन के साथ समाज को जागरूक करना भी जरूरी

मुंबई। टीवी अभिनेत्री ईशा सिंह इन दिनों अपने नए सीरियल जूही मुई को लेकर चर्चा में हैं। इस सीरियल में वह एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हैं, जो ऑटिज्म से जुड़ी चुनौतियों के बीच अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है। इसी बीच ईशा सिंह ने आईएएनएस से टेलीविजन की बदलती कहानियों, दर्शकों की नई पसंद और समाज से जुड़े विषयों पर अपनी राय पेश की।

उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल मनोरंजन करना ही काफी नहीं है, बल्कि शो के जरिए लोगों को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी हो गया है। ईशा सिंह ने कहा, समय के साथ टीवी की दुनिया तेजी से बदल रही है। पहले जहां सीरियल्स में केवल पारिवारिक रिश्तों और मनोरंजन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, वहीं अब ऐसे विषयों को भी जगह मिल रही है जो समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज के दर्शक पहले से ज्यादा जागरूक हैं और वे ऐसी कहानियां देखना पसंद करते हैं, जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। यही वजह है कि निर्माता और लेखक भी अब ऐसे विषय चुन रहे हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करें। उन्होंने

कहा, आज की युवा पीढ़ी टेलीविजन की कहानियों को नई दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रही है। अब वही शो ज्यादा पसंद किए जाते हैं, जिनमें मनोरंजन के साथ मैसेज भी हो। आखिरकार टीवी पर वही दिखाया जाता है जिसे दर्शक देखना चाहते हैं। अगर लोगों की पसंद बदलती है तो कार्यक्रमों की कहानियां भी बदलना स्वाभाविक है, इसलिए आज ऐसे विषयों पर काम किया जा रहा है जो समाज के अलग-अलग वर्गों से जुड़े हों और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ा सकें।

मेट्रो बाजार

भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जून में 54.2 रहा, इनपुट लागत में कम हुआ महंगाई का दबाव

नई दिल्ली। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जून में गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 54.2 पर रहा है। यह जानकारी एचएसबीसी फ्लैश इंडिया पीएमआई डेटा में बुधवार को दी गई। जब भी पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। इससे नीचे रहने पर आर्थिक गतिविधियों में गिरावट देखी जाती है। पीएमआई आंकड़ों के मुताबिक, इस महीने नए ऑर्डर और उत्पादन में वृद्धि धीमी रही। कई निर्माताओं ने मांग में सुधार की सूचना दी, जबकि अन्य ने ग्राहकों की कम मांग और बाजार प्रतिस्पर्धा को इसका कारण बताया। इस बीच, निर्यात मांग भी इस महीने सकारात्मक बनी रही, हालांकि वृद्धि की गति धीमी रही। एसएसबीसी की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी ने कहा कि जून के पीएमआई डेटा से पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा, ÷इस नरमी से पता चलता है कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव की वजह से आई शुरुआती तेजी के बाद अब मांग थोड़ी कम हुई है। आउटपुट, नए ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर और रोजगार में ग्रोथ धीमी हुई है, जबकि इनपुट और आउटपुट प्राइस इंडेक्स दोनों में गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि भू-राजनीतिक उथल-पुथल कम होने के साथ महंगाई का दबाव भी कम हो रहा है। पीएमआई डेटा के मुताबिक, इस महीने इनपुट और आउटपुट लागत में महंगाई का दबाव कम हुआ है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा की जून बिक्री में 37% की बढ़ोतरी, बिके 1.06 लाख से अधिक वाहन

नई दिल्ली। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) ने बुधवार को बताया कि जून 2026 में उसकी कुल ऑटो बिक्री 1,06,207 वाहनों की रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक है। इस आंकड़े में घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात भी शामिल है। कंपनी के अनुसार, जून में घरेलू बाजार में यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) की बिक्री 60,393 यूनिट रही, जो सालाना आधार पर 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाती है। वहीं, निर्यात सहित कुल यूटिलिटी व्हीकल बिक्री 61,504 यूनिट दर्ज की गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत गोल्लागुंटा ने कहा कि जून में कंपनी ने 60,393 एसयूवी और 3.5 टन से कम क्षमता वाले लाइट कमर्शियल व्हीकल (एलसीवी) की 26,076 यूनिट बेचीं, जिनमें क्रमशः 28 प्रतिशत और 35 प्रतिशत की मजबूत सालाना वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने बताया कि जून में कुल 5,918 वाहनों का निर्यात किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 125 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी को दर्शाता है। वहीं, कुल लाइट कमर्शियल व्हीकल (एलसीवी) बिक्री 39,896 यूनिट रही। एलसीवी सेगमेंट में भी कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा। 2 टन से कम क्षमता वाले एलसीवी की बिक्री 3,508 यूनिट रही, जिसमें 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं 2 टन से 3.5 टन क्षमता वाले एलसीवी की बिक्री 22,568 यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 35 प्रतिशत अधिक है। कंपनी के तीन पहिया वाहन (थ्री-व्हीलर) कारोबार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। जून 2026 में इस श्रेणी में 13,820 यूनिट की बिक्री हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने यह आंकड़ा 8,454 यूनिट था। इस तरह थ्री-व्हीलर बिक्री में 63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

'बम-बम भोले' के जयघोष के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना

जम्मू-कश्मीर एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज अमरनाथ यात्रा 2026 के पहले जत्थे को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने भगवती नगर बेस कैंप पर पहुंचकर यात्रियों से मुलाकात की और उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना की। श्रद्धालुओं ने भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और यात्रा को लेकर खासा उत्साह दिखाया। इस बार यात्रा के लिए बेहद कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम और बालटाल, दोनों रास्तों की निगरानी के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 670 कंपनियां तैनात की गई हैं। इससे एक दिन पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भगवती नगर स्थित यात्री निवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया था। उन्होंने श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधा, सुरक्षा प्रबंध, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्प डेस्क, सफाई व्यवस्था, बिजली-पानी की सप्लाई और आपात सेवाओं का निरीक्षण किया था।

आज टीवीके में शामिल होंगे एआईएडीएमके के दो पूर्व मंत्री

चेन्नई, एजेंसी। एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री डॉसी विजयभास्कर और

एमआर विजयभास्कर गुरुवार को लगभग 15,000 समर्थकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी के सत्ता में आने के बाद से यह इसमें शामिल होने वाले नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा समूह होगा। यह कार्यक्रम चेन्नई के पास मल्लापुरम के एक प्राइवेट होटल में होगा। टीवीके के वरिष्ठ नेता एन आनंद और अधव अर्जुन औपचारिक रूप से इन नेताओं और उनके समर्थकों का पार्टी में स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में एआईएडीएमके के कई जाने-माने पूर्व नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है।

शामिल होने वालों में तिरुचिरापल्ली की पूर्व मंत्री एस. वलारमथी, तिरुपुर के पूर्व मंत्री एम.एस.एम. आनंदन और पूर्व विधायक मनराज (श्रीविल्लिपुत्तूर), एम. रामकुमार (कुंभकोणम), राजावर्मन (तिरुचिरापल्ली), सत्यन प्रभाकर (परमाकुडी) और थिरुग्ननसंबंधनम (पेरावुरानी) शामिल हैं।

पश्चिम एशिया में संकट के बीच रूस बना भारत का सबसे भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार

कच्चे तेल के आयात में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, जून में बना नया रिकॉर्ड

एजेंसी,नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और ईरान-अमेरिका के बीच संघर्ष के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई थी। ऐसे समय में रूस ने भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। इसी का परिणाम है कि जून महीने में भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल की खरीद की। वस्तु विश्लेषण संस्था केप्लर के ताजा आंकड़ों के अनुसार, यह किसी भी जून महीने में भारत का अब तक का सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात है। इससे साफ हो गया है कि संकट की घड़ी में भारत और रूस के बीच ऊर्जा सहयोग पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। केप्लर के अनुसार, जून में भारत ने प्रतिदिन 49 लाख 30 हजार बैरल कच्चे तेल का आयात किया, जो इस महीने के लिए अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पश्चिम एशिया में आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच भारतीय तेल शोधन कंपनियों ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की खरीद की। जून में रूस से आयात बढ़कर 26 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया, जबकि मई में यह लगभग 19 लाख बैरल प्रतिदिन था। यानी केवल एक महीने में रूस से आयात में करीब 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक संकट के दौरान रूस ने भारत को ऊर्जा आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध और मजबूत हुए हैं। केप्लर के शोधन आपूर्ति एवं विश्लेषण प्रमुख सुमित रिटोलिया का कहना है कि रूस से बढ़ी खरीद यह दिखाती है कि भारतीय तेल शोधन कंपनियां अलग-अलग स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करने और लागत को संतुलित रखने में सफल रही हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने से बड़ी राहत

उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, भारत ने अगस्त तक कच्चे तेल और रसोई गैस की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। एक सरकारी तेल विपणन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के दोबारा सामान्य होने के बाद खाड़ी देशों से ऊर्जा आपूर्ति फिर शुरू हो गई है। इससे घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता को लेकर बनी चिंताएं काफी हद तक कम हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय तेल शोधन कंपनियां सामान्यतः एक से दो महीने पहले ही कच्चे तेल की खरीद तय कर लेती हैं। यही कारण है कि अगस्त तक की जरूरतों का बड़ा हिस्सा पहले ही सुनिश्चित किया जा चुका है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। रूस, अफ्रीकी देशों, वेनेजुएला और अन्य उत्पादक देशों से बढ़ते निर्यात के कारण भारत के पास अब पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं।

एक क्षेत्र पर निर्भरता घटाने की रणनीति

भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कच्चे तेल की खरीद का दायरा लगातार बढ़ाया है। अब रूस के अलावा ओमान, ब्राजील, अमेरिका, अंगोला, पश्चिम अफ्रीकी देशों और दक्षिण अमेरिका के कई उत्पादक देशों से भी कच्चा तेल खरीदा जा रहा है। इसका उद्देश्य किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करना और वैश्विम संकट की स्थिति में भी ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखना है। विश्लेषकों का मानना है कि निकट भविष्य में भारत द्वारा ईरान से कच्चे तेल की खरीद में कोई बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। इसकी वजह यह है कि भारत पहले ही कई देशों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति समझौते कर चुका है।

जयराम रमेश का मोदी सरकार पर हमला

वोट चोरी, सीट चोरी, अब चंदा चोरी, चुनाव आयोग भी बना एनडीए का हिस्सा

एजेंसी,नई दिल्ली

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष जयराम रमेश ने केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं और भाजपा सत्ता

बचाने के लिए हरसंभव राजनीतिक हथकंडे अपना रही है। रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी को माइनॉरिटी प्रधानमंत्री बताते हुए कहा कि उनकी सरकार सहयोगी दलों के सहारे चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित विवाद की सीबीआई जांच की मांग भी उठाई।

जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में ÷400 पार÷ का नारा दिया था, लेकिन अपने दम पर बहुमत तक हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई और सरकार आज चंद्रबाबू नायडू तथा नीतीश कुमार जैसे सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी हुई है। उनके मुताबिक, यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब माइनॉरिटी पीएम हैं। उन्होंने कहा कि मोदी अपनी तुलना पंडित जवाहरलाल नेहरू से करते हैं, जबकि नेहरू हर चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि 2024 के चुनाव के बाद आयोग की भूमिका निष्पक्ष नहीं रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को निष्पक्ष चुनाव में हराना मुश्किल था, इसलिए संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि रिटर्निंग अधिकारी ने राज्य सरकार के दबाव में फैसला लिया और चुनाव आयोग ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया।

राम मंदिर ट्रस्ट विवाद की सीबीआई जांच की मांग

राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित विवाद पर कांग्रेस नेता ने कहा कि ट्रस्ट सरकार की निगरानी में बना था और पूरे मामले की जानकारी शीर्ष नेतृत्व को थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कोई अनियमितता हुई है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए सवाल किया कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं।

कीव पर रूस का ड्रोन-मिसाइल अटैक होटल में आग लगने से आठ की मौत

कीव,नई दिल्ली

रूस और यूक्रेन के बीच बीते चार साल से ज्यादा समय से जारी भीषण संघर्ष दिन-प्रतिदिन और भयावह रूप लेता जा रहा है। यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमलों के बाद आज तड़के रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों और ड्रोन से एक बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में आठ लोगों की मौत हो गई। वहीं 39 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। रूस के इस बड़े हमले के बाद पूरी राजधानी धमाकों और आग की लपटों से दहल उठी। कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं और उनके मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इस हमले से कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने खुफिया जानकारी के हवाले से देशवासियों को आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि रूस राजधानी पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी में है, इसलिए लोग हवाई हमले के सायरन बजते ही सावधान हो जाएं। इसके बाद बुधवार देर रात जैसे ही सायरन गूंजे, लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने पालतू जानवरों और सोने के बैग के साथ मेट्रो स्टेशनों और बंकरों में छिप गए।

भारत ने पाक से 13 भारतीय कैदियों को राजनयिक पहुंच देने की मांग की

नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि अपने यहां हिरासत में बंद 13 सिविल कैदियों (जिनके भारतीय होने की संभावना है) को तुरंत कूटनीतिक पहुंच प्रदान करे। ये 13 व्यक्ति लंबे समय से पाकिस्तान में बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक उन्हें भारतीय दूतावास के अधिकारियों से मिलने की अनुमति नहीं दी है। भारत और पाकिस्तान हर छह महीने पर (एक जनवरी और एक जुलाई को) राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक-दूसरे की हिरासत में बंद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान करते हैं। यह 2008 के कूटनीतिक पहुंच समझौते के तहत किया जाता है। इस साल भारत की तरफ से पाकिस्तानी या पाकिस्तानी होने का संदेह वाले 386 सिविल कैदी और 53 मछुआरों की सूची सौंपी गई है, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय या भारतीय होने की संभावना वाले 52 सिविल कैदियों और 198 मछुआरों के नाम दिए हैं।

भरत भूषण मामले के आरोपी एसडीओ बने पटना में डीएसपी, भड़का परिवार

बिलौटी/शाहपुर। बिहार के चर्चित भरत भूषण एनकाउंटर मामले में आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा को सरकार ने पटना में नई जिम्मेदारी दी है। उन्हें अब मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का डीएसपी बनाया गया है। राजेश शर्मा को पटना में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद भरत के परिवार वालों ने काफी नाराजगी जताई है।

बता दें कि पुलिस द्वारा कथित एनकाउंटर में मारे गए बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी मामले में उनकी माता आशा देवी ने तत्कालीन जगदीशपुर एसडीपीओ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बावजूद सरकार द्वारा

उनका तबादला कर नई जगह पोस्टिंग दिए जाने पर भरत तिवारी के स्वजनों ने सवाल उठाए हैं। आशा देवी ने बयान जारी कर कहा कि जिन अधिकारी के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज है। उन्हें कार्रवाई के बजाय नई पोस्टिंग देना कई सवाल खड़े करता है।

गाजियाबाद में चार दोस्तों ने युवक को बर्थडे पार्टी में बुलाकर की हत्या

गाजियाबाद। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के न्यू शांति नगर में बुधवार देर रात 22 वर्षीय मोहित की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। स्वजन ने हत्या का आरोप उसके चार दोस्तों पर लगाया है। पुलिस ने मामले में तीन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी के लिए परिजनों ने विरोध जताते हुए जल निगम मार्ग पर जाम लगा दिया।

घटनास्थल पर पुलिस की जांच चल रही है। मौके पर फारेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। मुख्य आरोपित के घर और बाहर कई जगह खून के निशान मिले हैं। शुरुआती जांच में न्याय, देव, हरी और गौरव पंडित समेत कुल छह आरोपितों के नाम सामने आ रहे हैं।

मृतक के भाई मनीष का आरोप है कि करीब 20 दिन पहले मोहित का कुछ युवकों से विवाद हुआ था। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हो गया था। इसके बाद सभी खाटू श्याम और हरिद्वार घूमने गए थे। मनीष का कहना है कि उसी दौरान आरोपितों ने मोहित की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। मनीष के अनुसार, बुधवार रात आरोपितों ने मोहित को जन्मदिन की पार्टी में बुलाया। पार्टी में ही देर रात करीब ढाई बजे आरोपितों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए।

दोपहर मेट्रो

प्रदूषण नियंत्रण का मास्टर प्लान लागू हुआ

दिल्ली में बिना वैध पीयूसी ईंधन नहीं, जुर्माना भी बढ़ा

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने स्थायी मास्टर प्लान 1 जुलाई को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत अब बिना वैध पीयूसी के किसी वाहन को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, भारी जुर्माना भी लगेगा। बाहरी बीएस-6 से नीचे के वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी, पार्किंग शुल्क दोगुना होगा और दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही बुलाने की व्यवस्था लागू की जाएगी। यह पूरी व्यवस्था हर वर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगी। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण एवं वन विभाग के माध्यम से अधिसूचित दिशा-निर्देशों में वाहनों, निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा जलाने जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए स्थायी नियम तय किए हैं। सरकार का कहना है कि अब हर साल अलग-अलग आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी और सभी विभाग पहले से तय नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सबसे बड़ा बदलाव वाहनों को लेकर किया गया है। अब पूरे साल दिल्ली के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों पर केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन मिलेगा, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) प्रमाणपत्र होगा। पीयूसी की जांच केवल प्रमाणपत्र दिखाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वाहन डेटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी इसकी पुष्टि की जाएगी।

घर से काम को बढ़ावा

प्रदूषण के दौरान सड़क पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए दिल्ली सरकार और निजी कार्यालयों में भी बदलाव किया गया है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक एक समय में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे, जबकि बाकी कर्मचारी वर्क फॉम होम करेंगे। सरकारी विभागों में आवश्यक सेवाओं और वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यालय आने की अनुमति रहेगी। निजी संस्थानों को भी अलग-अलग शिफ्ट, कार पूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं।

पार्किंग महंगी कर निजी वाहनों पर रोक की कोशिश

दिल्ली में 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य लोगों को निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि दिल्ली मेट्रो की पार्किंग और पार्क-एंड-राइड सुविधा वाले स्थान इस व्यवस्था से बाहर रहेंगे। धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्माण गतिविधियों पर भी कड़ा नियंत्रण किया गया है। हर वर्ष 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल पैदा करने वाली तोड़फोड़ और खुले में होने वाले सिविल निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को इससे छूट मिलेगी, लेकिन निर्माण स्थलों को धूल नियंत्रण के सभी मानकों का पालन करना होगा।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक राजेश सिरोठिया द्वारा पी जी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,करोंद-भानपुर बाइपास विलेज रासलाखेड़ी भोपाल से मुद्रित तथा ए-182 मनीषा मार्केट शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। संपादक राजेश सिरोठिया स्थानीय संपादक अनिल शर्मा* आर एन आई पंजीयन क्रमांक एमपी एचआईएन/2016/68849 (*पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) फोन : 0755-7963564